राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण गुरुवार 13 अगस्त 2026 वर्ष-9,अंक-192 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

'शॉर्टकट' से दूर रहें 'रील युग' में रह रहे युवा

● पीएम मोदी ने जेन जी को दे दिया बड़ा खास मैसेज ● पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की आत्मकथा का किया विमोचन

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आत्मकथाएं पढ़ने और दूसरों के संघर्षों से सीखने की अपील की। उन्होंने कहा कि 'रील के युग' में रह रहे युवाओं को याद रखना चाहिए कि शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा 'ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक' माय लाइफ, माय स्ट्रगल्स' के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोविंद का जीवन दिखाता है कि दृढ़ संकल्प किसी व्यक्ति को मुश्किलों से उबरने और सर्वोच्च संवैधानिक

पद तक पहुंचने में कैसे मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी कोविंद के लगातार सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहने का जिक्र करते हुए कहा कि पद छोड़ने के बाद भी उन्होंने आराम नहीं किया। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद एक राष्ट्र, एक चुनाव पहल पर काम कर रहे हैं, जो भारतीय लोकतंत्र में एक नया अध्याय खोल सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि इस मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति के प्रयास भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में उनके निरंतर योगदान का हिस्सा हैं।

प्रधानमंत्री का मैसेज- शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज रील का जमाना है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको कहीं न कहीं खींच ले जाते हैं लेकिन इस दौर में भी, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात याद रखें। 'शॉर्ट कट' आपको नुकसान पहुंचा सकता है।

पीएम मोदी की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब सरकार और सत्तारूढ़ बीजेपी ने सोशल मीडिया पर 'जेन जी' से जुड़ने की कोशिशें तेज कर दी हैं। नीट पेपर लीक होने के खिलाफ पिछले महीने हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से कहा था कि वे युवाओं से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करें और रील 'पोस्ट' करें। हाल के हफ्तों में पीएम मोदी ने स्वयं युवाओं को संबोधित करते हुए कई बार रील साझा की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविंद की आत्मकथा भारतीय लोकतंत्र की धरोहर बनेगी और नयी पीढ़ी को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें भविष्य में और ऐसे कई युवाओं की जरूरत है जो कोविंद जी की तरह हों।

कोविंद के जीवन और संघर्ष का किया जिक्र

पीएम मोदी ने कहा कि आत्मकथा का शीर्षक बिल्कुल सही है क्योंकि रामनाथ कोविंद का जीवन और संघर्ष भले ही व्यक्तिगत थे, लेकिन उन संघर्षों की जीत भारतीय लोकतंत्र की है। उन्होंने याद किया कि बचपन में घर का सामान बचाने की कोशिश के दौरान लगी आग में कोविंद ने अपनी मां को खो दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दुखद घटना कोविंद को तोड़ सकती थी लेकिन इसके बजाय इसने उन्हें और मजबूत बनाया। पीएम मोदी ने कहा कि कोविंद में अच्छे संस्कार डालने में उनके पिता की अहम भूमिका रही। प्रधानमंत्री ने कोविंद के साथ की बात याद की।

संक्षिप्त समाचार

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का इस्तीफा

अगले साल फरवरी 2027 तक जिम्मेदारी संभालते रहेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने 12 अगस्त को इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा 18 अगस्त को होने वाली टाटा संस की एजीएम से ठीक पहले आया है। हालांकि, वे फरवरी 2027 तक पद पर बने रहेंगे। चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल को लेकर टाटा ट्रस्ट्स के साथ सहमति नहीं बन पाई थी। नए कारोबारों में भारी निवेश, उनके प्रदर्शन और टाटा संस के भविष्य को लेकर मतभेद इस फैसले की बड़ी वजह बने। एन चंद्रशेखरन के इस्तीफे की खबर के बाद टाटा ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में गिरावट है। टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंज्यूमर के शेयर 3 फीसदी तक नीचे हैं। चंद्रशेखरन ने कहा कि, टाटा संस के चेयरमैन के रूप में मेरा मौजूदा कार्यकाल 20 फरवरी 2027 को खत्म हो रहा है। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके मेरे अगले 5 साल के कार्यकाल के विस्तार की सिफारिश की थी। इसे टाटा संस की नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी और बोर्ड ने दर्ज किया था और आगे बढ़ाने की सिफारिश की थी। इसके बाद, यह प्रस्ताव 24 फरवरी 2026 को टाटा संस बोर्ड के सामने रखा गया था।

पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने बलूचिस्तान ढाया कहर

अंधाधुंध बमबारी,20 लोगों की मौत,सैकड़ों हुए बेघर

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में एक बार फिर हवाई हमले किए हैं। बलूच मीडिया ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने सोराब के गिदार इलाके के गोंधन में कई जगहों पर अंधाधुंध बमबारी की है। इसमें कम से कम 20 आम नागरिक मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। बमबारी की वजह से दर्जनों घर हमले में तब्दील हो गए हैं। पाकिस्तानी एयर फोर्स ने ऐसे समय में बलूचिस्तान में बमबारी

की है, जब प्रांत में पाक आर्मी और सरकार को लेकर गुस्सा चरम पर है। द बलूचिस्तान पोस्ट ने बताया है कि मंगलवार देर रात से बुधवार तड़के तक पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने प्रांत के कई हिस्सों में बम गिराए हैं। पाकिस्तानी आर्मी अक्सर अपने इन हमलों को विद्रोही गुटों के खिलाफ ऑपरेशन कहता है। वहीं बलूचिस्तान के स्थानीय संगठनों का कहना है कि आम गरीब लोगों के घरों को सेना के बमों का निशाना बनाया गया है। इसने ना सिर्फ आम लोगों की जान ली है बल्कि उनको बेघर भी कर दिया है।

आईएसआई से जुड़ा पाकिस्तानी जासूस बांग्लादेश बॉर्डर से गिरफ्तार

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने बुधवार को भारत-बांग्लादेश बॉर्डर से संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया। उसके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलीजेंस से संबंध हैं। वह जासूसी और आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार आतंकी की पहचान राना रऊफ के रूप में हुई है। भारत में वहाब आलम के नाम से रह रहा था। बांग्लादेश भागने की कोशिश में था। उसे 24 परगना जिले के बनगांव से गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के अनुसार, रऊफ मूल रूप से पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है। वह 2012 में नेपाल के रास्ते भारत आया था। इसके बाद से पश्चिम बंगाल में रहने लगा।

● अखिलेश यादव बोले-पूरा विपक्ष खिलाफ, रिजिजू ने दी दलील

एफसीआरए बिल जेपीसी भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में हुआ पास

नई दिल्ली (एजेंसी)। एफसीआरए संशोधन विधेयक पर घमासान के बीच सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार इस बिल को संसद की 31 सदस्यीय जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव किया है। एफसीआरए संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रस्ताव सदन में पेश किया।

● **विपक्ष ने बिल का किया विरोध, जेपीसी में भेजा गया प्रस्ताव**- विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए)को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का सरकार विपक्षी सांसदों ने समर्थन किया है। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एफसीआरए बिल को जेपीसी में भेजने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी रणनीति के तहत आगे भी अपने मुद्दे उठाता रहेगा।

एफसीआरए बिल पर जमकर हंगामा

लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने जैसे ही एफसीआरए बिल पेश किया तो सदन में हंगामा बढ़ गया। कांग्रेस ने एक सुर में इस बिल को वापस लेने की मांग उठाई। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि पूरा विपक्ष इस बिल के खिलाफ है। यह बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। इस बिल को सदन में पेश नहीं किया जाना चाहिए। इस पर किरेन रिजिजू ने तर्क किया।

भारी बारिश से पानी-पानी हुए एमपी और राजस्थान

कई जगह बाढ़ जैसे हालात, काशी में 100 मंदिर डूबे

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पानी भरा,हालात बद्तर

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के मध्य और पूर्वी हिस्से में मानसून ऐक्टिव है। मध्यप्रदेश, राजस्थान के कई इलाकों में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश से हालात खराब हैं। इसकी वजह तीन मानसूनी सिस्टम हैं। इनके कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से बड़ी मात्रा में नमी आ रही है। भोपाल में बुधवार को लगातार तीसरे दिन स्कूलों में छुट्टी है। यहां दो दिनों में 8.57 इंच बारिश हुई। करीब

200 मकानों में ढाई फीट तक पानी भर गया। रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी और इंदौर में अगले 24 घंटे में यहां 4 इंच से ज्यादा बारिश का अनुमान है। उधर, राजस्थान में खोखी बांध की दीवार टूटने से 300 बीघा फसल खराब हो गई है। कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे की टनल के एक हिस्से में दो-तीन फीट तक पानी भरा हुआ है। वहीं, उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। इसके चलते जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार को पानी भर गया था।

यूपी में उफनाती नदी में स्कॉर्पियो सवार 6 लोग बहे

पहाड़ों पर हो रही जोरदार बारिश से यूपी में गंगा, यमुना और शारदा समेत 10 नदियां उफान पर हैं। सहारनपुर में शाहपुर गाड़ा नदी पर बना पुल डूब गया। मंगलवार शाम को पुल पर स्कॉर्पियो कार फंस गई। स्कॉर्पियो सवार 6 लोग कार सहित बहने लगे। किसी तरह कार से कूदकर लोगों अपनी जान बचाई। बाद में आसपास के लोगों ने ट्रैक्टर से कार बाहर निकाली। वाराणसी में घाटों की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। सभी 84 घाटों को आपस में जोड़ने वाले रास्ते जलमग्न हो गए हैं। 100 से ज्यादा छोटे मंदिर डूब गए हैं। मणिकर्णिका घाट पर 50 फुट ऊंचा रत्नेश्वर महादेव मंदिर आधे से ज्यादा डूब चुका है। सिर्फ गुंबद दिखाई दे रहा। हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह स्थल डूब गया है। घाट की ऊपरी सीढ़ियों पर चिताएं जलाई जा रही हैं। उन्नाव में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। कॉलोनियों में नदी का पानी घुसने से गलियों में नावें चल रही हैं। वहीं, फर्रुखाबाद और बिजनौर के 45 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 31 घर गंगा नदी में समा चुके हैं। मथुरा और आगरा में यमुना नदी का पानी घाटों की सीढ़ियां डूब गई हैं। वृंदावन में केशीघाट का परिक्रमा मार्ग जलमग्न हो गया है।

शराबबंदी पर लगा प्रतिबंध हटाएगी सम्राट सरकार!

बिहार में नई रिपोर्ट से शुरू हुई बहस,राजद का दावा-बिना सर्वे के हुआ लागू

पटना (एजेंसी)। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के करीब एक दशक बाद एक शोध रिपोर्ट ने इस नीति को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। देश के प्रमुख आर्थिक शोध संस्थानों में शामिल नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीईआर) की एक स्टडी में बिहार में पूर्ण शराबबंदी खत्म कर नियंत्रित तरीके से शराब की बिक्री शुरू करने और आबकारी कर व्यवस्था बहाल करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा होने पर राज्य के अपने राजस्व में करीब 14 से 15 फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट में शराबबंदी के बाद अवैध शराब की तस्करी, दूसरे नशीले पदार्थों के इस्तेमाल और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है।

36 साल पुराने कश्मीरी पंडित मर्डर केस में एसआईए की छापेमारी

1990 में आतंकियों ने पिता-पुत्र की हत्या की थी,शव पेड़ से लटके मिले थे

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए) ने बुधवार को 1990 के कश्मीरी पंडित पिता-पुत्र हत्याकांड में 9 जगह तलाशी ली। इनमें जम्मू, बारामूला, शोपियां, अनंतनाग शामिल हैं। मामला कश्मीरी पंडित लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता सरवनंद कौल प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र कौल के अपहरण और हत्या से जुड़ा है। दोनों अनंतनाग के कोकरनाग स्थित सोफ शाली के रहने वाले थे। 1990 में केस अनंतनाग के डोरू थाने में दर्ज हुआ था। अब इसकी जांच एसआईए कर रही है। कश्मीरी पंडित कवि सरवनंद कौल प्रेमी और उनके 27 साल के बेटे वीरेंद्र कौल को 29 अप्रैल 1990 की रात हथियारबंद आतंकियों ने उनके घर से किडनैप किया था। इसके कुछ दिन बाद, 1 मई 1990 को दोनों के शव एक पेड़ से लटके मिले थे। इससे पहले काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर ने 8 अगस्त को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग, शोपियां और बारामूला जिलों में कई जगह एक साथ तलाशी ली थी। अनंतनाग के हिलर शाहाबाद इलाके में एक घर की तलाशी के दौरान डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस फारुक अहमद के नेतृत्व वाली टीम ने दो डिजिटल डिवाइस जब्त किए थे।

रांची पहुंचते ही 360 डिग्री घूम गया छात्र आंदोलन

अब निशाने पर आ गए राहुल,संसद से सड़क तक संग्राम

रांची (एजेंसी)। दिल्ली से रांची पहुंचते-पहुंचते छात्र आंदोलन का रुख 360 डिग्री घूम गया है। जहां दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर कांग्रेस, केंद्र सरकार पर हमलावर थी, वहीं झारखंड में छात्र आंदोलन पर हुए लाठीचार्ज के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मोर्चा संभाल लिया है।

इस सियासी बदलाव के साथ ही संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ गया है और अब निशाने पर राहुल गांधी आ गए हैं।

छात्रों का इस्तेमाल कर रहे राहुल गांधी: बीजेपी

संसद में केंद्र और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर अपने एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए छात्रों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। साथ ही, पार्टी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के आंदोलन पर विस्तृत चर्चा के दौरान जवाब देने के लिए पहले ही तैयार हैं।

ट्रम्प ने माना-ईरान के डर से बदलना पड़ा प्लेन

हमला होता तो एयरफोर्स वन पर होता

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मान लिया है कि उन्होंने पिछले महीने तुर्किये में ईरान के डर से प्लेन बदला था। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे जिस प्लेन से समिट में हिस्सा लेने गए थे उस पर हमले का सबसे ज्यादा खतरा था। ट्रम्प ने यह भी बताया कि उन्हें सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट के केटरिंग ट्रक में बैठाकर दूसरे विमान तक ले जाया गया। ट्रम्प ने कहा- अगर कोई हमला होता तो उसी प्लेन को निशाना बनाया जाता। मैं वही करता हूं, जो सुरक्षा एजेंसियां कहती हैं। मुझे लगातार धमकियां मिलती रहती हैं। ट्रम्प कैमरों के सामने वन में सवार हुए थे।

दूध की जगह वनस्पति से बना पनीर एमपी में बैन

सीएम ने जारी किया आदेश,महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ पहले लगा चुके प्रतिबंध

भोपाल (एजेंसी)। महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुजरात रवाना होने से पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की बैठक में इसके उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश दिए। बता दें कि एनालॉग पनीर को असली दूध से बने पनीर के विकल्प के तौर पर तैयार किया जाता है। इसमें दूध की जगह या दूध के साथ वनस्पति वसा, स्टार्च और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कम कीमत के कारण बाजार में इसकी खपत तेजी से बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। जैसा अन्य राज्यों ने लगाया है। हम प्राकृतिक रूप से दुग्ध उत्पादन को बढ़ाएंगे और प्राकृतिक रूप से ही पनीर बनाएंगे।

रोज 300 से 400 क्विंटल की खपत का अनुमान

मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर की रोजाना आवक और बिक्री करीब 300 से 400 क्विंटल होने का अनुमान है। इस हिसाब से प्रदेश में हर महीने करीब 9 हजार से 12 हजार क्विंटल, यानी 900 से 1200 टन एनालॉग पनीर खपने की बात सामने आई है। बड़ी मात्रा में इसकी बिक्री को देखते हुए सरकार ने अब इस पर सख्ती का निर्णय लिया है।

मानवाधिकार आयोग ने भी जताई नाराजगी

एनालॉग पनीर की बिक्री को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी नाराजगी जताई है। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों को पत्र लिखने का फैसला किया है। आयोग की ओर से राज्यों से इस तरह के उत्पाद की बिक्री और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर जानकारी मांगे जाने की संभावना है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि एनालॉग पनीर घातक है। इसके लिए एफएसएस एआई को नोटिस देकर पूछ रहे हैं कि इस तरह के पनीर को बेचने की इजाजत क्यों दे रहे हैं। कानूनगो ने कहा कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अंगदान की संस्कृति ही मानवता को नई दिशा दे सकती है

(लेखक- ललित गर्ग)

(विश्व अंगदान दिवस (13 अगस्त 2026) पर विशेष)

मनुष्य जीवनभर अपने लिए बहुत कुछ अर्जित करता है-धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, संबंध और सुविधाएँ। लेकिन जीवन की अंतिम घड़ी में इन सबका महत्व समाप्त हो जाता है। तब यदि हमारे शरीर का कोई अंग किसी दूसरे मनुष्य की धड़कन बन जाए, हमारी आँखें किसी अंधेरे जीवन में रोशनी भर दें, हमारा यकृत या गुर्दा किसी परिवार के बुझते चिराग को फिर से जला दे, तो इससे बड़ी जीवन-सार्थकता और क्या हो सकती है? अंगदान मृत्यु के बाद भी जीवन को जारी रखने की वह मानवीय संभावना है, जो मनुष्य को केवल अपने लिए जीने वाले प्राणी से उठाकर मानवता के लिए जीने वाला बना देती है। विश्व अंगदान दिवस हमें इसी महान विचार से जोड़ता है। आज आवश्यकता केवल अंगदान के बारे में जानकारी देने की नहीं, बल्कि हमारी सोच बदलने की है। हमें यह प्रश्न अपने आप से पूछना होगा कि जिस शरीर को मृत्यु के बाद पंचतत्व में विलीन होना है, उसके उपयोगी अंग यदि किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन दे सकते हैं तो उन्हें अपने साथ मिट्टी में मिला देना अधिक सार्थक है या किसी की सांसों का हिस्सा बना देना? मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन का कारण बनना हमारे हाथ में है।

भारत की सांस्कृतिक स्मृति में शरीर और जीवन के महान त्याग की परंपरा बहुत पुरानी है। महर्षि दधीचि की कथा इसका सबसे प्रभावशाली उदाहरण है। पौराणिक परंपरा के अनुसार जब देवताओं को असुरों से संघर्ष के लिए ऐसे अस्त्र की आवश्यकता हुई जिसे दधीचि की अस्थियों से बनाया जा सके, तब महर्षि दधीचि ने लोककल्याण के लिए अपना शरीर ही त्याग दिया। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया और उससे जनकल्याण की रक्षा हुई। यह कथा आधुनिक अर्थों में अंगदान की चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं है, लेकिन अपने शरीर को भी समाज और सृष्टि के कल्याण के लिए समर्पित कर देने की भारतीय त्याग-चेतना का अत्यंत शक्तिशाली प्रतीक अवश्य है। भारत के राष्ट्रपति सचिवालय ने भी अंग एवं देहदान की भारतीय परंपरा को समझाते हुए महर्षि दधीचि के इस प्रसंग का उल्लेख किया है। हमारी परंपरा में राजा शिवि की कथा भी त्याग और जीव-दया की अद्भुत मिसाल है। एक कबूतर की रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर का मांस तक देने की तत्परता दिखाई। चाहे ये प्रसंग धार्मिक आख्यान हों, लेकिन इनके भीतर छिपा संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है-अपने जीवन और शरीर को केवल अपनी निजी संपत्ति न समझना, बल्कि उसे व्यापक जीवन के कल्याण से जोड़ना। जैन दर्शन का सूत्र 卐परस्परोपग्रहो जीवानाम्卐 भी यही बताता है कि जीव एक-दूसरे के उपकार के लिए हैं। अंगदान इस विचार का आधुनिक वैज्ञानिक रूप कहा जा सकता है।

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने इस मानवीय भावना को वास्तविक जीवन बचाने की शक्ति प्रदान कर दी है। वर्ष 1954 में दुनिया का पहला सफल मानव किडनी प्रत्यारोपण हुआ। रोनाल्ड ली हेरिक ने अपनी एक किडनी अपने जुड़वां भाई रिचर्ड को दान की थी। यह घटना चिकित्सा इतिहास में एक ऐसी क्रांति की शुरुआत बनी, जिसने आगे चलकर अंग प्रत्यारोपण को लाखों लोगों के लिए जीवन की आशा बना दिया। इसके बाद 1967 में मानव हृदय प्रत्यारोपण की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि चिकित्सा विज्ञान मनुष्य की मृत्यु और जीवन के बीच खड़ी कई दीवारों को तोड़ सकता है। भारत ने भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय यात्रा की है। देश में पहला सफल किडनी प्रत्यारोपण 1 दिसंबर 1971 को चेन्नई के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर में हुआ था। उस समय शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन भारत में हजारों लोगों के लिए अंग प्रत्यारोपण जीवन का नया द्वार बनेगा। आज चिकित्सा तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि किडनी, लिवर, हृदय, फेफड़े, अग्न्याशय और आंत जैसे अंगों के साथ कॉर्निया, त्वचा, हड्डी और हृदय वाल्व जैसे ऊतकों का भी प्रत्यारोपण संभव है।

लेकिन विज्ञान की क्षमता जितनी बढ़ी है, हमारी सामाजिक चेतना उस गति से नहीं बढ़ पाई। यही सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में आज भी प्रत्यारोपण की आवश्यकता और उपलब्ध अंगों के बीच बड़ा अंतर है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2024 में देश में अंग प्रत्यारोपण की गतिविधि व्यापक रही, लेकिन मृतक दाताओं की संख्या अभी भी आवश्यकता की तुलना में बहुत कम है। इसका अर्थ साफ है-हमारे अस्पतालों में तकनीक है, डॉक्टर हैं, सर्जरी की क्षमता है, लेकिन जीवन बचाने के लिए पर्याप्त अंग नहीं हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए हमें अंगदान को मृत्यु की चर्चा नहीं, जीवन की चर्चा बनाना होगा। परिवारों में इस विषय पर समय रहते बातचीत होनी चाहिए। स्कूलों, विश्वविद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और मीडिया को मिलकर ऐसी वातावरण-निर्मिति करनी होगी जिसमें अंगदान सुनते ही भय नहीं, बल्कि करुणा और जीवन बचाने का भाव पैदा हो।

आज भी अनेक लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर को क्षति पहुँचाना धर्म के विरुद्ध है। कुछ लोगों को अगले जन्म की चिंता होती है, कुछ को शरीर के साथ होने वाली चिकित्सा प्रक्रिया का भय होता है और कुछ परिवार अंतिम समय में मानसिक रूप से इतने टूट जाते हैं कि अंगदान का निर्णय नहीं ले पाते। इन भ्रमों का समाधान टकराव से नहीं, संवाद, संवेदना और वैज्ञानिक जानकारी से होगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझनी होगी कि अंगदान किसी पर थोपा जाने वाला धार्मिक या सामाजिक कर्तव्य नहीं है। यह एक स्वैच्छिक, नैतिक और मानवीय निर्णय है, जिसे व्यक्ति को विश्वसनीय चिकित्सा एवं कानूनी जानकारी के आधार पर लेना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से यह संकल्प करता है कि मृत्यु के बाद उसके उपयोगी अंग किसी जरूरतमंद को मिलें, तो वह अपने जीवन की अंतिम घड़ी को भी मानवता के उत्सव में बदल सकता है।

भारत में अंगदान की प्रेरक घटनाएँ लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में नागपुर में 52 वर्षीय शिक्षक कोंडबा दत्तात्रेय मडावी मृतक अंगदान करने वाले 200वें दाता बने, उनके अंगों से तीन लोगों को नया जीवन मिला। ऐसी घटनाएँ हमें बताती हैं कि अंगदान कोई दूर की आदर्शवादी कल्पना नहीं, बल्कि हमारे आसपास घटने वाली वास्तविक जीवन-बचाने वाली प्रक्रिया है। दिल्ली में 70 वर्षीय मृत महिला के गुर्दों का सफल उपयोग कर एक 56 वर्षीय महिला को जीवन की नई उम्मीद मिली-यह घटना यह भी बताती है कि केवल उम्र के आधार पर किसी संभावित दाता के अंगों को अनुपयोगी मान लेना उचित नहीं है, अंतिम निर्णय चिकित्सा स्थिति पर निर्भर करता है। भारत के कुछ राज्यों ने इस दिशा में उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तेलंगाना में 2024 में मृतक अंगदान की दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक रही और उसके 'जीवदान' कार्यक्रम के माध्यम से हजारों प्रत्यारोपण संभव हुए। तमिलनाडु में भी मृतक अंगदान की व्यवस्था ने अनेक परिवारों को प्रेरित किया हैय 2026 में एक परिवार ने भाषा की बाधा के बावजूद डिजिटल अनुवाद की मदद से अपने प्रियजन के अंगदान का निर्णय लिया और अनेक मरीजों को जीवन मिला।

ये घटनाएँ बताती हैं कि जहाँ संवेदना, व्यवस्था और जागरूकता मिलती हैं, वहाँ मृत्यु भी कई जीवनों को बचाने का माध्यम बन सकती है।

अंगदान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह रक्तदान से भी आगे की परोपकार-चेतना है। रक्तदान में हम अपने शरीर की ऐसी चीज देते हैं जिसे शरीर फिर बना लेता है, अंगदान में हम मृत्यु के बाद ऐसी अमूल्य संपदा देते हैं जिसका उपयोग किसी दूसरे शरीर को जीवन देने के लिए हो सकता है। इसलिए अंगदान को केवल चिकित्सा की भाषा में नहीं, मानवीय रिश्तों और करुणा की भाषा में समझना होगा। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि किसी एक दाता का निर्णय कई लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अंगदान केवल एक व्यक्ति की मदद नहीं, बल्कि कई परिवारों में आशा का संचार है। किसी की आँखों में रोशनी, किसी की छाती में धड़कता हृदय, किसी की सांसों में फेफड़ों की शक्ति और किसी के शरीर में काम करता हुआ नया अंग-यह सब किसी अनजान व्यक्ति की उदारता का परिणाम हो सकता है।

इसलिए अंगदान को मृत्यु के बाद शरीर का अंत मानने वाली सोच से बाहर निकालकर 'मृत्यु के बाद भी जीवन देने' की अवधारणा से जोड़ना होगा। मृत्यु अंधेरा है, लेकिन अंगदान उस अंधेरे में जलाया गया दीपक है। एक दीपक स्वयं जलता है, लेकिन उसका प्रकाश दूसरों को दिखाई देता है। इसी तरह दाता संसार से चला जाता है, लेकिन उसके अंग किसी और की सांस, धड़कन या दृष्टि बनकर जीवन को रोशन करते रहते हैं। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति वह नहीं जो बैंक में जमा है, न वह जो तिजोरी में बंद है और न वह जो हमारे नाम पर दर्ज है। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति वह है जिसका उपयोग हमारे बाद भी किसी जीवन को बचाने में हो सके।

इस विश्व अंगदान दिवस पर हमें केवल यह संकल्प नहीं लेना चाहिए कि 'अंगदान करेंगे', बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़कर यह संकल्प लेना चाहिए कि अंगदान के बारे में अपने परिवार से बात करेंगे, भ्रम दूर करेंगे और समाज में जीवन बचाने वाली इस चेतना को फैलाएँगे। क्योंकि जीवन का अंतिम अध्याय मृत्यु नहीं होना चाहिए।

वह किसी दूसरे के जीवन की नई शुरुआत भी बन सकता है। आइए अपने जीवन की अंतिम विरासत मानवता के नाम करें। अंगदान का दीप जलाएँ, ताकि किसी की बुझती जिंदगी में उजाला हो। अपनी मृत्यु को किसी दूसरे की जिंदगी का कारण बनाएँ-क्योंकि इससे सुंदर मृत्यु और इससे सार्थक जीवन शायद ही कोई हो।

'शरीर चला जाए, पर उसकी करुणा जीवित रहे।
सांसें रुक जाएं, पर किसी और की सांसें चलती रहें।
यही अंगदान है, यही मानवता का महादान है।'

संपादकीय

पैलेट के जख्म

इसमें दो राय नहीं कि किसी आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों के किन्हीं परिस्थितियों में उग्र होने और जन-धन की हानि रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन को कार्रवाई करनी होती है। इसमें भी दो राय नहीं है कि राज्य के पास हिंसा को रोकने और कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का भी है कि लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे विरोध को रोकने के लिए प्रयोग की गई ताकत का स्तर क्या रहा। जाहिर है राष्ट्रविरोधी ताकतों, हिंसक भीड़ तथा छात्रों के आंदोलन को एक ही तौर-तरीके से नहीं निपटा जा सकता है। इसी आलोक में सवाल पैदा होता है कि जंतर-मंतर से शुरू हुए संसद चलो मार्च को रोकने के लिए इस्तेमाल की गई ताकत क्या जरूरी थी? क्या उचित तरीके से अधिकृत थी? ऐसा ही विवाद इस आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर खड़ा हुआ है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने शुरुआत से ही पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया। जबकि बाद में जनरल डायरी में यह दर्ज किया गया कि रैपिड एक्शन फोर्स ने एंटी-रायट गन से दो राउंड फायरिंग की थी। वहीं दूसरी ओर छात्र प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग को लेकर विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं। खासकर, कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्ष ने गृह मंत्री पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर तीखे प्रहार किए हैं। वे बाकायदा गृह मंत्री के इस्तीफे को लेकर लगातार अभियान चलाते रहे हैं। इसी बीच सूचना के अधिकार के तहत दिल्ली के दो अस्पतालों से एकत्र की गई जानकारी के अनुसार बीस जुलाई को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कम से कम दस लोगों को पैलेट गन से चोट लगी थी। इन अस्पतालों में पैलेट गन से आहत छात्रों ने उपचार कराया था। निस्संदेह, पैलेट गन से घायल होने वालों का यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि यह एक आधिकारिक रिकॉर्ड पर आधारित है, न कि किसी बिना पुष्टि वाले दावों पर आधारित है। दरअसल, पैलेट गन की जद में आये छात्रों के अनुभव परेशान करने वाले रहे हैं। खबरों के अनुसार, कुछ प्रदर्शनकारियों के चेहरों, छाती और आंखों पर चोट आई है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि एक छात्र की आंख की रोशनी भी जा सकती है। सार्वजनिक विमर्श में सवाल उठाये जाते रहे हैं कि छात्र आंदोलनकारियों के विरुद्ध पैलेट गन का इस्तेमाल करने का तार्किक आधार क्या है। वहीं दूसरी ओर कानून-व्यवस्था बनाये रखने के दौरान मेटल पैलेट गन पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कहा था कि मौजूदा नियमों के तहत विशेष परिस्थितियों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे हथियार रखने की कानूनी वैधता और किसी खास घटना में इनके गलत इस्तेमाल के आरोपों के बीच फर्क किया है। निस्संदेह, इस फर्क की सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए। इसके इस्तेमाल के बाद किसी तरह का विवाद न हो, इसलिए स्थिति को साफ करने के लिए पारदर्शिता अपनाना भी बेहद जरूरी है। इससे जुड़े कई तथ्यों को लेकर सावधानी बरती जानी चाहिए, जिसमें गोला-बारूद का पर्याप्त रिकॉर्ड रखना, सीसीटीवी फुटेज, बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग, वायरलेस की बातचीत का रिकॉर्ड और साथ ही मेडिकल रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाना जरूरी है। साथ ही इन तथ्यों की स्वतंत्र जांच की जानी भी जरूरी है। वहीं दूसरी ओर सरकार का भी दायित्व बनता है कि भीड़ को काबू करने में पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े तमाम नियम स्पष्ट रूप से बताए जाएं।

जंतर मंतर- रांची: छात्र आंदोलन एक रूप अनेक

(लेखिका- निर्मल रानी)

देश इन दिनों लगभग राष्ट्रव्यापी छात्र आक्रोश व आंदोलन से रूबरू है। अभी कुछ दिन पहले ही नीट पेपर लीक और राष्ट्रीय परीक्षाओं में हुई धांधली के ख़िलाफ़ 6 जून से शुरू होकर 25 जुलाई 2026 तक चला आंदोलन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के बाद ख़त्म हुआ था। इसके बाद ही झारखंड में भी जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरुद्ध 29 जुलाई से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई। यहाँ भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, धांधली और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच आदि मांगों को लेकर धरना, प्रदर्शन और विधानसभा घेराव जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं। परन्तु कुछ दिनों पूर्व हुये दिल्ली के जंतर-मंतर व वर्तमान समय रांची में चल रहे छात्र आंदोलन में जहां कुछ बातें समान हैं वहीं कई बातें विरोधाभासी भी हैं। उदाहरण के तौर पर दोनों ही आंदोलन पेपर लीक और राष्ट्रीय परीक्षाओं में हुई धांधली व अनियमितताओं के ख़िलाफ़ किये गए हैं। जंतर मंतर की ही तरह रांची में भी जहाँ आंदोलनस्थल पर अनेक स्वयंसेवी लंगर चला रहे हैं व आंदोलनकारी छात्रों के दूर दराज़ बैठे समर्थक फूड ऐप्स के जरिए सीधे आंदोलन स्थल पर भोजन ऑर्डर कर रहे हैं व छात्रों को मेडिकल व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ भी भोजन इतनी अधिक मात्रा में आ रहा है कि आंदोलनकारी छात्रों ने वीडियो जारी कर लोगों से कुछ दिन ऑर्डर रोकने की अपील की ताकि खाना बर्बाद न हो और बचे हुए भोजन को ज़रूरतमंदों में बांटा जा सके। इसके अलावा रांची के स्थानीय दुकानदारों और आम नागरिकों द्वारा आंदोलन स्थल पर भोजन,समोसे, बिरयानी,नाश्ता और पानी आदि पहुंचाया जा रहा है। अनशन पर बैठे छात्र नेताओं की सेहत की देखभाल के लिए रांची के सदर अस्पताल में मेडिकल टीम नियमित रूप से आंदोलन स्थल पर पहुंचकर स्वास्थ्य जांच (ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल) कर रही है। इसके अतिरिक्त झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफ़ान अंसारी ने निर्देश जारी किया है कि आंदोलन के दौरान बीमार या चोटिल होने वाले छात्रों के इलाज का पूरा ख़र्च राज्य सरकार उठाएगी, चाहे वे सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं या निजी अस्पताल में।

परन्तु इन दोनों अर्थात दिल्ली व रांची के आंदोलन में जो सबसे बड़ा विरोधाभास नज़र आ रहा है वह है जंतर मंतर के छात्र आंदोलन का विरोध करने वालों का रांची के आंदोलन में बढ़चढ़कर हिस्सा लेना। बड़ी हैरत की बात है कि जो वर्ग,जो संगठन और जिस विचारधारा से जुड़े लोग जंतर मंतर के आंदोलनकारियों को देशद्रोही, बदतमीज़, गटर जनरेशन,गलियां बोलने व अपशब्द इस्तेमाल करने वालों का झुण्ड,विदेशी फ़ंडिंग से चलने वाला आंदोलन बता रहे थे, दिल्ली के आंदोलन में जो लोग हिन्दू-मुस्लिम का दृष्टिकोण ढूंढ रहे थे,जिन्हें दिल्ली के आंदोलन कारी आवारा व चरित्रहीन नज़र आ रहे थे वही लोग वही वर्ग और वही विचारधारा रांची के छात्र आंदोलन में कुछ इसतरह बढ़चढ़कर हिस्सा लेने को उतावली है गोया रांची का आंदोलन छात्र आंदोलन के बजाये देश का दूसरा स्वाधीनता संग्राम हो? याद कीजिये कि जंतर मंतर आंदोलन के संदर्भ में ही एक हिंदुत्व विचारक और केरल भाजपा के बौद्धिक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रमुख टीजी मोहनदास ने कहा था कि अगर स्थिति उनके नियंत्रण में होती, तो वे नई दिल्ली के आंदोलन स्थल के आसपास कर्फ़्यू लगाकर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवा देते। इस व्यक्ति ने प्रदर्शन में शामिल धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी विचारधारा वाली छात्राओं व महिलाओं के साथ रेप करवाने जैसी बेहद अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की थीं। साथ ही गोदी मीडिया के नाम से बदनाम सत्ता का पिछलग्गू मीडिया भी जो जंतर मंतर आंदोलन से या तो मुंह मोड़े हुआ था या इसी आंदोलन विरोधी वर्ग की तरह आंदोलन में केवल नकारात्मकता तलाश रहा था,जिसे संसद भवन के पास चल रहा इतना बड़ा छात्र आंदोलन नज़र नहीं आ रहा था वही मीडिया रांची में डेरा जमाये हुये है और अपने तरीक़े से छात्र आंदोलन का नरेटिव सेट करने में लगा है। इस दोहरेपन का केवल एक ही कारण है कि दिल्ली में केंद्र व दिल्ली राज्य, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जबकि झारखण्ड में झारखंड मुक्ति मोर्चा , कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, के गठबंधन यानी इण्डिया गठबंधन की सरकार है और झामुमो के हेमंत सोरेन इस सरकार के मुख्यमंत्री हैं। इसलिये इनका समर्थन छात्र आंदोलन को नहीं बल्कि यह झारखण्ड में इण्डिया गठबंधन की सरकार का विरोध कर रहे हैं।

इस अवसरवादी विचारधारा का विरोध करने वालों का चेहरा रांची में उस समय भी बेनक़ाब हुआ जबकि जंतर मंतर के आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा और वहां अनशन पर बैठने वाली अखिल भारतीय छात्र संगठन्‌ढ्ढऋ की केंद्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा जब हज़ारों छात्रों के साथ विधानसभा के लिये मार्च निकाल रही थीं उस समय एक युवक ने नेहा पर स्याही फेंक कर छात्र आंदोलन को समर्थन देने की अपनी हक़ीक़त को उजागर कर दिया। घटना के तुरंत बाद मौक़े पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों ने युवक को पकड़कर उसकी पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया। नेहा बोरा ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिनके पास तर्क या बहस की क्षमता नहीं होती, वे ऐसी हरकतों पर उतर आते हैं। उन्होंने इस हमले के पीछे भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोगों का हाथ होने का आरोप लगाया। ग़ौरतलब है कि नेहा बोरा व उनका संगठन अखिल भारतीय छात्र संगठन्‌ढ्ढऋ जंतर मंतर के

जो नहीं है उसे पाना हो ध्येय

असंतुष्ट होने का अर्थ दुखी होना नहीं है। असल में कोई आदमी पूरी तरह सुखी होकर भी असंतुष्ट हो सकता है। सुखी होने का मतलब है, जो है, उसे आनंद से भोगना। और असंतुष्ट होने का अर्थ है- जो नहीं है उसे आनंद से पैदा करने का श्रम करना। जब अधिकतम लोग समाज में इस भांति श्रम करते हैं तो समाज संपन्न और समृद्ध होता है। और जब अधिक लोग ऐसा सोचते हैं कि जो है बस ठीक है, वही रुक जाना है, तो फिर पूरा समाज धीरे-धीरे दरिद्र हो जाता है। जिंदगी का सारा विकास, जो नहीं है, उसे पाने से ही होता है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि ऐसा किसी जगह मानने की जरूरत नहीं है कि अब सब पूरा हो गया, अब भला मुझे क्या करना है! यह मरने के ढंग हैं। यह अपने भीतर जिंदा रहते हुए मर जाना है।

जब तक श्वास है, तब तक एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता हो कि मेरी तो सच में ही सारी आवश्यकताएं पूरी हो गईं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को दूसरों की आवश्यकताएं पूरा करने में लग जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को पक्का ऐसा लगता है कि मेरी तो सभी आवश्यकताएं पूरी हो गईं, मैं क्यों श्रम करूं? तो उसे चारों तरफ देखना चाहिए कि अब मेरा काम तो जमीन पर खत्म हो गया, लेकिन दूसरों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं, उनके लिए मैं श्रम करने में लग जाऊं।

लेकिन श्रम से नहीं बचा जा सकता। आपकी अपनी आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं, तो अपने चारों तरफ देखिए। बहुत लोगों की पूरी नहीं हुई हैं, अत- उनके लिए श्रम करने में लग जाइए। लेकिन खाली बैठने का हक किसी को नहीं है। संन्यासी को भी खाली बैठने का हक नहीं है। देश को संपन्न करना है तो सभी को श्रम में लगना ही चाहिए। और श्रम में हम तभी लगेंगे जब कोई आवश्यकता पूरी करनी हो। चाहे अपनी, चाहे किसी दूसरे की, लेकिन आवश्यकता पूरी करने की दौड़ जारी रहनी चाहिए। यह दौड़ शांत हो, यह दौड़ आनंदपूर्ण हो, इतना मैं कहूंगा। यह दौड़ पागल की नहीं होनी चाहिए, विक्षिप्त की नहीं होनी चाहिए। यह दौड़ नींद को हराम कर देने वाली नहीं होनी चाहिए। यह दौड़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आदमी बिल्कुल होश खो दे और दौड़ता रहे, और उसे पता भी न हो कि कहां दौड़ रहा है। यह दौड़ बहुत आनंदपूर्ण होनी चाहिए, यह दौड़ बहुत शांत होनी चाहिए, यह दौड़ बहुत स्वस्थ होनी चाहिए। यह हो सकती है। लेकिन हमने इस तरफ सोचा नहीं

विचार मंथन

चीन की जमीन हड़पने की भूख कभी खत्म नहीं होगी

(लेखक- सनत जैन)

अरुणाचल पर चीन का कब्जा बढ़ता जा रहा है। 3 जिलों में चीन के सैनिक घुस गए हैं। भारतीय क्षेत्र में चीन ने स्थायी निर्माण कर लिये हैं। वहां की जनता शिकायतें कर रही हैं। इसके बाद भारत का विदेश मंत्रालय सक्रिय हुआ। भारत सरकार ने कहा अरुणाचल भारत का हिस्सा था, आगे भी बना रहेगा। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद स्वतंत्रता के बाद से ही चल रहा है, लेकिन पिछले एक दशक में चीन ने जिस सुनयोजित तरीके से भारत की सीमा से लगे हिस्सों पर कब्जा किया है। भारत सरकार की चुप्पी से यह मामला अब गंभीर हो गया है। चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद 8 दशकों से चल रहा है। चीन ने पहले भारत के साथ हिंदी चीनी भाई-भाई का नारा देकर विश्वासघात किया और भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया। 1962 के युद्ध में जब भारत आर्थिक एवं सामरिक रूप से बहुत कमजोर था। तत्कालीन भारत सरकार ने युद्ध लड़ा, और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। 1950 में तिब्बत पर चीनी नियंत्रण होने के बाद भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का हर संभव प्रयास किया। 1959 में दलाई लामा को भारत में शरण दी, जिसके कारण 1962 का युद्ध भी हुआ। चीन और भारत के बीच युद्ध के बाद चीन ने भारत के साथ सीमा का विवाद जारी रखा। 1962 के युद्ध के बाद चीन की कभी हिम्मत नहीं हुई, वह भारतीय भूमि पर कब्जा कर सके। 1971 में इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद से चीन ने कभी भी भारत की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। सीमा विवाद को लेकर जरूर विवाद बना रहा। भारत सरकार ने भी चीन के साथ संबंधों को बनाए रखा, सीमा पर भारत हमेशा सतर्क रहा।

पिछले कुछ वर्षों से चीन ने अरुणाचल और सीमावर्ती राज्यों में सुनियोजित तरीके से टुकड़े-टुकड़े में कब्जा करने की कोशिश की। भारत सरकार ने चीन की इस कार्रवाई का खुलकर विरोध नहीं किया। पिछले एक दशक में चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंध लगातार बढ़ते चले गए। वर्तमान सरकार के चीन के साथ व्यापारिक और राजनीतिक रिश्ते बढ़ते रहे। इसके बाद भी सीमा पर तनाव बढ़ता चला गया। भारतीय सीमावर्ती राज्यों में चीन का कब्जा बढ़ने तथा सेना के साथ भिड़ंत होने, भारतीय सैनिकों की शहादत होने के बाद, भारत सरकार का संसद में यह कहना, चीन ना घुसा है, ना भारत की किसी भूमि पर कब्जा हुआ है। इसके बाद चीन को शह मिली, भारत के विदेश मंत्री का सार्वजनिक रूप से यह कहना, चीन की अर्थव्यवस्था भारत से बहुत बड़ी है। हम चीन के साथ लड़ाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भारत के सीमावर्ती इलाकों पर चीन ने अपनी घुसपैठ बढ़ा दी। अरुणाचल के तीन जिलों में चीनी सैनिक लगातार अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। कब्जा कर रहे हैं। भाजपा सांसद और अरुणाचल के लोग कई बार इसकी शिकायत भारत सरकार और जिला प्रशासन से कर चुके हैं। इसके बाद भी भारत सरकार की चुप्पी सभी को आश्चर्यचकित कर रही है। चीन के साथ पिछले वर्षों में जिस तरह से संघ और भाजपा नेताओं का मेल-जोल बढ़ रहा है। चीन के साथ भारत का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। चीन से आयात ज्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है। व्यापार घाटा बहुत बढ़ गया है, इसके बाद भी भारत सरकार चुप है। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर होगा। वर्तमान सरकार भारतीय हितों की उपेक्षा कर रही है। अब तो अति हो गई है, अरुणाचल के तीन जिलों के नागरिक खुलकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। इतने संवेदनशील मामले में भारत सरकार की चुप्पी से भारत की सुरक्षा और सीमाएं दोनों ही खतरे में है।

भारत के रिश्ते अपने पड़ोसी देशों के साथ केवल इसलिए कमजोर हो गए हैं, भारत अब चीन से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में पड़ोसी देशों ने चीन के साथ अपने रिश्ते बना लिए, भारत के साथ पड़ोसी देशों के रिश्ते काफी कमजोर हो गए हैं। भारत के राष्ट्रीय हित और संप्रभुता खतरे में आ गई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, पहली बार केंद्र में कमजोर सरकार है, जो चीन के कब्जे को रोक नहीं पा रही है। वर्तमान सरकार के राजनीतिक नेतृत्व को चीन यह मानकर चल रहा है, सरकार चीन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेगी। इसलिए वह मनमानी कर रहा है।

युलु ने सीरीज सी फंडिंग में जुटाए 9.3 करोड़

अगले दो साल में बेड़ा 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा

मुंबई ।

इलेक्ट्रिक परिवहन मंच युलु ने अपने सीरीज सी वित्त पोषण दौर में 9.3 करोड़ रुपये सफलतापूर्वक जुटा लिए हैं। इस पूंजी के साथ कंपनी ने अगले दो वर्षों में अपने इलेक्ट्रिक वाहन बेड़े को चार गुना बढ़ाकर 2 लाख करने, सेवा नेटवर्क के विस्तार और शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की अपनी योजनाओं को तेज करने का लक्ष्य रखा है। युलु के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने बताया कि यह वित्तपोषण कंपनी के कारोबारी मॉडल की मजबूती और मांग की व्यापक संभावनाओं की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि युलु भारत की शहरी स्थानीय परिवहन गतिविधियों की आधारशिला के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने और शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बजाज ऑटो और मैग्ना इंटरनेशनल इंक जैसी रणनीतिक साझेदारियों ने युलु को विशेष हार्डवेयर, प्रौद्योगिकी और व्यापक ऊर्जा बुनियादी ढांचे वाला एक एकीकृत इलेक्ट्रिक वाहन परिवेश बनाने में मदद की है। अब कंपनी युलु एक्सप्रेस के साथ शहरी लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भी प्रवेश करने की योजना बना रही है। यह ई-कॉमर्स, बाइक टैक्सी और त्वरित पार्सल डिलीवरी के लिए डिज़ाइन किया गया एक उच्च क्षमता वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। कंपनी का उद्देश्य इन विस्तार योजनाओं के माध्यम से टिकाऊ शहरी गतिशीलता में अपनी स्थिति मजबूत करना है।

आरडी इंडस्ट्रीज का शेयर करीब 39 प्रतिशत बढ़त के साथ सूचीबद्ध

नई दिल्ली ।

आरडी इंडस्ट्रीज का शेयर बुधवार को शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत के साथ सूचीबद्ध हुआ। कंपनी के शेयर ने अपने 53 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले करीब 39 प्रतिशत की शानदार बढ़त दर्ज की, जिससे निवेशकों को लिस्टिंग के दिन ही उल्लेखनीय मुनाफा हुआ। कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को निवेशकों से भारी प्रतिक्रिया मिली थी। बीएसई पर आरडी इंडस्ट्रीज का शेयर 73.60 रुपये पर कारोबार शुरू किया, जो इसके निर्गम मूल्य से 38.86 प्रतिशत अधिक है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर यह 35.84 प्रतिशत की बढ़त के साथ 72 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। इस दमदार प्रदर्शन के साथ कंपनी का बाजार पूंजीकरण 2,119.10 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। कंपनी के 426 करोड़ रुपये के आईपीओ को निवेशकों ने हाथों-हाथ लिया था और पिछले सप्ताह शुक्रवार को बोली के अंतिम दिन यह 133.66 गुना से अधिक अभिदान के साथ बंद हुआ था। 50-53 रुपये प्रति शेयर के मूल्य दायरे वाले इस आईपीओ ने बाजार में कंपनी की सर्कुलर इकोनॉमी आधारित व्यावसायिक मॉडल की स्वीकार्यता को दर्शाया है। आरडी इंडस्ट्रीज ऊर्जा भंडारण उत्पादों और गैर-लौह धातु कबाड़ के पुनर्चक्रण तथा अपशिष्ट से महत्वपूर्ण संसाधनों को पुनः प्राप्त करने का काम करती है।

ओला इलेक्ट्रिक को 7,240 करोड़ का पीएलआई लाभ

मंत्रालय ने बढ़ाई सेल उत्पादन प्रोत्साहन समयसीमा

नई दिल्ली ।

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड को भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) से बड़ी राहत मिली है। मंत्रालय ने कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी ओला सेल टेक्नोलॉजीज (ओसीटी) के लिए उन्नत रसायन सेल उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की समयसीमा में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से ओला इलेक्ट्रिक को अपने 20 गीगावाट आवंटन के लिए 2031 तक पूरे पांच साल की पीएलआई अवधि मिलेगी, जिससे उसे कुल 7,240 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन लाभ प्राप्त हो सकेगा। कंपनी ने बुधवार को बताया कि यह प्रोत्साहन राशि अगली तिमाही से तिमाही आधार पर मिलनी शुरू हो जाएगी। ओला इलेक्ट्रिक के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक भविष अग्रवाल ने कहा कि संशोधित समयसीमा महज विस्तार से कहीं अधिक है; यह उनके सेल कारोबार की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल देती है। फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक के पास 2.5 गीगावाट की स्थापित सेल विनिर्माण क्षमता है, जिसमें 3.5 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ी जा रही है। कंपनी ने कहा कि चालू तिमाही के अंत तक उसकी क्षमता 6 गीगावाट हो जाएगी, जो दिसंबर 2026 की संशोधित समयसीमा से काफी पहले शुरुआती स्थापित क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लेगी। लिथियम सेल इलेक्ट्रिक परिवहन, ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 188 अंक, निफ्टी 35 अंक गिरा

मुम्बई।

भारतीय शेयर बाजार बुधवार को गिरावट पर बंद हुआ। बाजार में ये गिरावट दुनिया भर के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। गत दिवस भी बाजार गिरावट पर बंद हुआ था। आज दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 187.90 अंक नीचे आकर 77,966.35 और 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 35.75 अंक फिसलकर 24,435.95 पर बंद हुआ। आज आईटी शेयरों में आई गिरावट का प्रभाव भी बाजार पर पड़ा है। कारोबार के दौरान सूचकांकों में निफ्टी आईटी में सबसे अधिक गिरावट रही। इसके बाद निफ्टी एफएमसीजी , निफ्टी कंजप्शन , निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.45 , निफ्टी हेल्थकेयर , निफ्टी ऑटो , निफ्टी सर्विसेज 0.14 और निफ्टी कमोडिटीज के शेयरों में भी गिरावट रही।

दूसरी ओर निफ्टी पीएसयू बैंक , निफ्टी मीडिया, निफ्टी इंडिया डिफेंस 0.70 , निफ्टी मेटल 0.54, निफ्टी पीएसई , निफ्टी इन्फ्रा और निफ्टी एनर्जी तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं व्यापक बाजार में मिलाजुला कारोबार हुआ। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार की कमजोर शुरुआत हुई। आज सुबह निफ्टी करीब 80 अंक गिरकर 24400 के नीचे आ गया, जबकि सेंसेक्स लगभग 250 अंकों की गिरावट के साथ 77900 के नीचे कारोबार करता दिखा।

वस्तु निर्यात दूसरी तिमाही में 131 अरब डॉलर पार करेगा- एग्जिम बैंक

नई दिल्ली ।

भारत के निर्यात-आयात बैंक (एग्जिम बैंक) ने एक सकारात्मक अनुमान जारी करते हुए कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में देश का कुल वस्तु निर्यात 131.2 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।

बैंक के बुधवार को जारी बयान के अनुसार यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 17.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत है। एग्जिम बैंक के विश्लेषण के मुताबिक इस वृद्धि में गैर-तेल निर्यात का बड़ा योगदान होगा, जिसके 20.3 प्रतिशत बढ़कर 113.8 अरब डॉलर होने की संभावना है।

इसी तरह, गैर-तेल और गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात में भी 20.5 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि का अनुमान है, जिससे यह आंकड़ा 105.8 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्र निर्यात वृद्धि को गति प्रदान कर रहे हैं और वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है। इस अनुमान से देश की व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

रुपया बढ़त पर बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बुधवार को भारतीय रुपया तीन पैसे की बढ़त के साथ ही 95.33 पर बंद हुआ। इससे पहले आज सुबह रुपया छह पैसे नीचे आकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.42 पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की मुख्य वजह होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बनी अनिश्चितता है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.40 प्रति डॉलर पर खुला। बाद में यह फिसलकर 95.42 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव के मुकाबले छह पैसे की गिरावट दिखाता है। वहीं रुपया मंगलवार को छह पैसे टूटकर 95.36 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.05 फीसदी की बढ़त के साथ 99.87 पर रहा।

बैंकिंग में एआई का जिम्मेदारी से करें इस्तेमाल- आरबीआई गवर्नर

बैंक के फैसलों की जिम्मेदारी अंततः बैंक की ही होती है, न कि उसके एल्गोरिद्म की

नई दिल्ली ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की नसीहत दी है। एफआईबीएसी 2026 सम्मेलन को संबोधित करते हुए मल्होत्रा ने साफ कहा कि एआई को नियंत्रित किए जाने वाले जोखिम के बजाय एक क्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए जिसका सावधानी से उपयोग हो। साथ ही उन्होंने कड़े शब्दों में आगाह किया कि बैंक के फैसलों की जिम्मेदारी अंततः बैंक की ही होती है, न कि उसके एल्गोरिद्म की।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि ब्रिक्स देशों के सदस्य तेज भुगतान प्रणाली को केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) से जोड़ने पर भी चर्चा कर रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने एआई मॉडल से जुड़े जोखिमों पर बोलते हुए कहा कि आरबीआई इसे क्षमता के रूप में देखता है। हालांकि, उन्होंने चेताया कि बैंकिंग प्रणाली में एआई अपनाने से मानवीय निर्णय क्षमता और जवाबदेही कम होने का जोखिम हो सकता है।

मल्होत्रा ने जोर दिया, हम यह नहीं कह सकते कि फैसला मॉडल ने किया। इसमें सार्थक मानवीय निगरानी, फैसले को समझाने और हस्तक्षेप करने की क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने इसे ब्लैक बॉक्स समस्या बताते हुए कहा कि एआई सिस्टम के किसी छोटे व्यवसाय को कर्ज न देने की सलाह देने पर, ऋणदाता और नियामक दोनों को कारण जानने का हक है। मल्होत्रा ने एआई में पक्षपात और भेदभाव के जोखिम पर भी आगाह किया, खासकर अगर वह पुराने कर्ज के आंकड़ों पर आधारित हो।

उन्होंने थर्ड-पार्टी वेंडर पर निर्भरता और डेटा गोपनीयता के खतरों का भी जिक्र किया, कहा कि ग्राहकों को डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा कानून के पालन से कहीं ज्यादा की उम्मीद करनी चाहिए।

आरबीआई गवर्नर ने भारतीय बैंकों को एआई अपनाने में पीछे न रहने पर जोर देते हुए कहा कि वैकल्पिक डेटा जैसे नकदी प्रवाह और जीएसटी फाइलिंग पर प्रशिक्षित एआई मॉडल ऋण आवंटन की लागत को कम कर सकते हैं।

सेबी का प्रस्ताव: कमोडिटी डेरिवेटिव में एफपीआई की बढ़ेगी भागीदारी, खुलेंगे नए रास्ते

इन बदलावों से बाजार में तरलता, मूल्य खोज और वैश्विक बाजारों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित

नई दिल्ली ।

बाजार नियामक सेबी ने एक्सचेंज-ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की भागीदारी बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य गैर-कृषि इंडेक्स डेरिवेटिव्स और नकदी के बिना सेटल होने वाले गैर-कृषि जिंस डेरिवेटिव्स में एफपीआई को व्यापार की अनुमति देना है। सेबी का मानना है कि इन बदलावों से बाजार में तरलता, मूल्य खोज और वैश्विक बाजारों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित होगा।

मंगलवार को जारी अपने परामर्श पत्र में सेबी ने दो प्रमुख प्रस्ताव रखे हैं। पहले प्रस्ताव के तहत, एफपीआई को अब गैर-कृषि इंडेक्स डेरिवेटिव अनुबंधों में भाग लेने की अनुमति मिलेगी, भले ही इनकी अंतर्निहित संपत्तियां नकदी में सेटल होती हों या नहीं। वर्तमान में, एफपीआई केवल नकदी में सेटल होने वाले गैर-कृषि डेरिवेटिव अनुबंधों में ही निवेश कर सकते हैं।

चूंकि इंडेक्स डेरिवेटिव्स का निपटान हमेशा नकदी में ही होता है, इसलिए यह बदलाव डिलीवरी से जुड़ी कोई समस्या पैदा नहीं करेगा। कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी (सीडीएसी) ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है।

दूसरे प्रस्ताव में एफपीआई को घरेलू एक्सचेंजों पर उपलब्ध फिजिकली सेटल होने वाले गैर-कृषि जिंस डेरिवेटिव्स में भी भागीदारी की इजाजत देने की बात कही गई है। इनमें कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, चांदी और आधार धातु जैसे वैश्विक बेंचमार्क से जुड़े जिंस शामिल हैं। सेबी के अनुसार, इससे बाजार में प्रतिभागियों का आधार और तरलता बढ़ेगी, साथ ही भारत का कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार अंतरराष्ट्रीय जिंस बाजार से गहराई से जुड़ सकेगा।

हालांकि, एफपीआई को टेंडर अवधि शुरू होने से पहले (एक्सपायरी से तीन दिन पूर्व) अपने निवेश को बेचना या रोल-ओवर करना होगा।

ऐसा न कर पाने पर उनकी खुली पोजीशन स्वचालित रूप से किसी ट्रेडिंग मेंबर के खातों में हस्तांतरित हो जाएंगी।

टाटा संस के चेयरमैन पद से एन. चंद्रशेखरन ने दिया इस्तीफा

फरवरी 2027 तक पूरा करेंगे कार्यकाल

मुंबई ।

टाटा ग्रुप में एक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिला है। एन. चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है, हालांकि वह फरवरी 2027 तक अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करेंगे और दोबारा नियुक्ति नहीं मांगेंगे। इस निर्णय के पीछे टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा की आपत्तियां और टाटा संस व टाटा ट्रस्ट्स के बीच गहरे मतभेद प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। नोएल टाटा ने फरवरी में उनकी दोबारा नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद यह फैसला टाल दिया गया था। दोनों संस्थाओं के बीच बोर्ड प्रतिनिधित्व, रणनीति और शापूरजी पल्लोनजी समूह की हिस्सेदारी जैसे मुद्दों पर मतभेद थे। चंद्रशेखरन 1987 में टाटा ग्रुप से जुड़े थे और 2017 में टाटा संस के चेयरमैन बने थे। यह इस्तीफा 18 अगस्त की एजीएम से ठीक पहले आया है, जहां उनकी दोबारा नियुक्ति पर शेयरधारकों की वोटिंग होनी थी। यह कदम टाटा ग्रुप के शीर्ष नेतृत्व में एक अहम बदलाव है।

अंबानी 25.8 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान पर

बिड़ला परिवार से तीन गुना ज़्यादा संपत्ति, टॉप 300 व्यवसायों की कुल वैल्यू 138 लाख करोड़ रुपए

नई दिल्ली

बार्कलेज और हुरुन इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर परिवारों की सूची में अंबानी परिवार शीर्ष पर है। उनकी कुल संपत्ति 25.8 लाख करोड़ रुपये है, जो दूसरे स्थान पर मौजूद कुमार मंगलम बिड़ला परिवार की संपत्ति से लगभग तीन गुना अधिक है। यह रिपोर्ट देश में पारिवारिक व्यवसायों की बढ़ती आर्थिक शक्ति को रेखांकित करती है। रिपोर्ट बताती है कि भारत के 300 शीर्ष पारिवारिक व्यवसायों की कुल वैल्यू 138 लाख करोड़ रुपये थी। कुमार मंगलम बिड़ला परिवार 8.1 लाख करोड़ रुपये और जिंदल परिवार 8 लाख करोड़ रुपये के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। पिछले एक साल में इन तीनों परिवारों की संपत्ति 1.57 लाख करोड़ रुपए बढ़ी, कुल मूल्यांकन 42 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा, जो देश के सूचीबद्ध बाजार पूंजीकरण का लगभग 9 फीसदी है। शीर्ष 10 में शामिल होने के लिए आवश्यक मूल्यांकन एक साल में 14 फीसदी बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इस दौरान, वेदांत के अनिल अग्रवाल परिवार मूल्यांकन में 74.7 फीसदी वृद्धि के साथ तीन पायदान ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर आ गया। वहीं, एचसीएल टेक का नाडर और विप्रो का प्रेमजी परिवार रैंकिंग में नीचे खिसके, क्रमशः 38 और 2.3 फीसदी गिरावट के बाद अब आठवें और नौवें स्थान पर हैं। पहली पीढ़ी के सबसे धनी परिवारों में अदाणी परिवार 19.57 लाख करोड़ रुपये के साथ सबसे आगे है। उसके बाद भारती एयरटेल के सुनील भारती मित्तल (12.1 लाख करोड़) और सन फार्मा के दिलीप सांघवी (4.54 लाख करोड़) का परिवार है। इन 300 फैमिली समूहों ने पिछले दो सालों में औसतन हर दिन 4,076 करोड़ रुपये की संपदा जोड़ी है, और 54 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है।

बैंकों में 2.31 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के फ्रॉड, वसूली केवल 2.7 फीसदी

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों में खुलासा- 2021-26 के बीच 1 करोड़ से अधिक के 5,607 मामले

नई दिल्ली ।

वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत आंकड़ों ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों में बड़े वित्तीय फ्रॉड की चिंताजनक तस्वीर पेश की है। वित्तीय वर्ष 2021 से 2026 के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक के कुल 5,607 धोखाधड़ी मामलों में 2,31,710.12 करोड़ रुपए की रकम शामिल थी, जिसमें से महज 6,283.14 करोड़ रुपए की ही वसूली हो पाई।

यह दर्शाता है कि 2,25,426.98 करोड़ रुपए की बड़ी राशि अभी भी फंसी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, जहां 2021 से 2024 तक बड़े फ्रॉड के मामलों और राशि में गिरावट देखी गई, वहीं वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 में इनमें तेज उछाल आया। ` वित्त वर्ष 24 में 641 मामलों के साथ 9,080.50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई, जो छह साल का निचला स्तर था। हालांकि,`` वित्त वर्ष 25 में यह संख्या बढ़कर 941 और` वित्त वर्ष 26 में 1,330 हो गई, जो` वित्त वर्ष 24 के मुकाबले दोगुने से भी अधिक है।`` वित्त वर्ष 26 में धोखाधड़ी की राशि भी बढ़कर 46,559.84 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले वर्ष से लगभग 55 फीसदी अधिक है। कुल मिलाकर, पांच सालों में 2.31 लाख करोड़ से अधिक के फ्रॉड में केवल 2.7 फीसदी (6,283.14 करोड़ रुपए) की ही वसूली हो सकी है। हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम नुकसान नहीं है और कानूनी तथा रिकवरी प्रक्रियाओं के जरिए भविष्य में भी कुछ रकम वापस मिल सकती है।

टाटा कैपिटल का रिवॉल्विंग क्रेडिट एक्सपोजर 5 फीसदी से कम

आरबीआई के नए प्रस्ताव से कंपनी पर पड़ेगा सीमित असर

नई दिल्ली ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को रिवॉल्विंग क्रेडिट स्कीम बंद करने के प्रस्ताव से टाटा कैपिटल पर नाम मात्र का असर पड़ेगा। कंपनी ने स्पष्ट किया कि उनके कुल ऋण पोर्टफोलियो में रिवॉल्विंग क्रेडिट का हिस्सा 5 फीसदी से भी कम है, जबकि इस कदम से बजाज फाइनेंस जैसी अन्य एनबीएफसी को बड़ी चुनौती मिल सकती है। टाटा कैपिटल के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने एक बैंकिंग सम्मेलन में बताया कि वे आरबीआई के इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देंगे और अंतिम विनियमन का पालन करेंगे। रिवॉल्विंग क्रेडिट एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था है जिसमें एक तय सीमा तक बार-बार पैसे उधार लेने और चुकाने की अनुमति होती है। जून के अंत तक टाटा कैपिटल का सकल ऋण 2.86 लाख करोड़ रुपये था। आरबीआई का यह कदम एवरग्रीनिंग के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से है, जहां उधारकर्ता नए ऋण से पुराने ऋण चुकाते हैं। एनबीएफसी की स्व-नियामक संस्था वित्तीय उद्योग विकास परिषद (एफआईडीसी) भी इस सप्ताह इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। विश्लेषकों का अनुमान है कि इस प्रस्ताव से बजाज फाइनेंस सर्वाधिक प्रभावित होगी। आईआईएफएल कैपिटल के मुताबिक, उसकी लचीली ऋण योजनाएं समेकित एयूएम का लगभग 15 फीसदी और स्वतंत्र ऋण पोर्टफोलियो का 20 फीसदी बनाती हैं। तुलनात्मक रूप से, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर 1 फीसदी से भी कम है, जबकि एलएंडटी फाइनेंस और पूनावाला फिनकॉर्प के लिए यह नगण्य है।

ग्रामीण भारत और छोटे व्यवसायों को एआई से सशक्त करें- एसबीआई चेयरमैन

तकनीक की वास्तविक परीक्षा बारीकियों में नहीं, उपलब्धियों में

नई दिल्ली ।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने बैंकिंग क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग को ग्रामीण ग्राहकों, छोटे व्यवसायों और कृषि तक गहरा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। शेट्टी ने स्पष्ट किया कि एआई की वास्तविक परीक्षा उसकी बारीकियों में नहीं, बल्कि उससे हासिल होने वाली उपलब्धियों में है। उन्होंने जोर दिया कि एआई को अर्थव्यवस्था में गहराई तक ले जाना होगा, खासकर ग्रामीण भारत, छोटे कारोबारियों और पारंपरिक ऋण मॉडल में शामिल न होने वाले ग्राहकों तक। उन्होंने बताया कि एआई कृषि क्षेत्र में जोखिम आकलन, डिजिटल रिकॉर्ड और सैटेलाइट इमेज के माध्यम से ऋण पहुंच और पोर्टफोलियो प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि, शेट्टी ने स्वीकार किया कि कुछ एआई तकनीकों को कृषि ऋण में पहले से अपनाया जा रहा है, लेकिन चुनौती उन्हें पायलट प्रोजेक्ट से आगे ले जाकर अंतिम छोर तक किफायती और व्यावहारिक बनाने की है। उन्होंने आगाह किया कि एआई के बढ़ते उपयोग से साइबर सुरक्षा जैसे नए जोखिम उत्पन्न होंगे, क्योंकि यह हमलावरों को अधिक परिष्कृत खतरे विकसित करने की अनुमति दे सकता है। बैंकों को अपनी सुरक्षा मजबूत करनी होगी और विश्वास बनाए रखने के लिए अपने ढांचे पर पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि एआई सिस्टम अधिक स्वायत्त हो जाएंगे।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

भारत सितंबर में अफगानिस्तान से खेलेगा तीन मैचों की टी20 सीरीज; बांग्लादेश को क्यों लगा झटका!

मुंबई। भारतीय क्रिकेट टीम सितंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। बीसीसीआई और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को संयुक्त बयान जारी कर सीरीज की घोषणा की। सीरीज के तीनों मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहला टी20 13 सितंबर, दूसरा 15 सितंबर और तीसरा मुकाबला 17 सितंबर को होगा। यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच पूरी टी20 सीरीज पांच दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी। इस एलान के साथ ही बांग्लादेश की भारत के खिलाफ सितंबर में प्रस्तावित लंबे समय से लंबित सफेद गेंद की सीरीज की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सीरीज पिछले साल टल गई थी। बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के कारण दोनों टीमों के बीच प्रस्तावित सीरीज को स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद बांग्लादेश ने सितंबर में भारत के खिलाफ सीरीज की मेजबानी का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, अब सितंबर के लिए भारत का कार्यक्रम अफगानिस्तान के खिलाफ तय हो गया है। ऐसे में बांग्लादेश की उस सीरीज को लेकर उम्मीदें लगभग खत्म होती नजर आ रही हैं।

भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के सभी मुकाबले एक ही मैदान पर खेले जाएंगे। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम को तीनों मैचों की मेजबानी मिली है।

बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास को समर्थन देने और उसके खिलाड़ियों को उच्च स्तर पर खेलने के मौके देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय क्रिकेट टीमों को नियमित रूप से मजबूत विरोधी टीमों के खिलाफ खेलने और अनुभव हासिल करने का अवसर देता है। बीसीसीआई के मानद सचिव देवजीत सैकिया ने भी भारत-अफगानिस्तान क्रिकेट संबंधों को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि दोनों टीमों के बीच पिछले कुछ वर्षों में नियमित द्विपक्षीय मुकाबले हुए हैं। सैकिया ने याद दिलाया कि भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले टेस्ट की मेजबानी की थी। इसके बाद दोनों टीमों के बीच अलग-अलग फॉर्मेट में लगातार मुकाबले होते रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग: बाबर आजम की टॉप-10 में एंट्री

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा बुधवार को जारी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉप-10 में धमाकेदार एंट्री की है। बाबर को वेस्टइंडीज दौरे पर उनकी शानदार बल्लेबाजी का इनाम मिला है। वेस्टइंडीज दौरे पर 2 टेस्ट मैचों की 4 पारियों में 2 अर्धशतक की मदद से 193 रन बनाने वाले बाबर पांच स्थान की छलांग लगाते हुए आईसीसी की टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में दसवें स्थान पर पहुंच गए हैं। शीर्ष 10 में बाबर एकमात्र पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं। टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के हैरी ब्रूक, तीसरे स्थान पर इंग्लैंड के जो रूट, चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, पांचवें स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के टेंबा बावुमा, छठे स्थान पर श्रीलंका के कामिंडु मेंडिस, सातवें स्थान पर भारत के शुभमन गिल, आठवें स्थान पर न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र, और नौवें स्थान पर भारत के यशस्वी जायसवाल हैं। श्रीलंका के दिनेश चांदीमल एक स्थान नीचे खिसकते हुए टॉप-10 से बाहर हो गए हैं। वह 11वें वें स्थान पर हैं। टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। शीर्ष 10 में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहले, न्यूजीलैंड के मैट हेनरी दूसरे, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क तीसरे, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस चौथे, दक्षिण अफ्रीका के मार्को जानसेन पांचवें, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बोलैंड छठे, और दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा सातवें स्थान पर हैं। रबाडा को एक स्थान का फायदा हुआ है। पाकिस्तान के नोमान अली एक स्थान के नुकसान के साथ सातवें स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड नौवें और ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन दसवें स्थान पर हैं।

टी20 सीरीज गंवाने के बावजूद पाकिस्तानी महिला खिलाड़ियों की रैंकिंग में सुधार

दुबई। आईसीसी ने ताजा महिला टी20 प्लेयर रैंकिंग जारी की है। भले ही पाकिस्तान ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज 1-2 से गंवाई, लेकिन इसके बावजूद नाशरा संधू, शवाल जुल्फिकार और तुबा हसन की रैंकिंग में शानदार सुधार हुआ है। नाशरा संधू ने श्रीलंका के विरुद्ध तीसरे टी20 मैच में 17 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था। संधू गेंदबाजों की रैंकिंग में एक स्थान ऊपर चढ़कर आठवें पायदान पर पहुंच गई हैं। बाएं हाथ की स्पिनर ने इस सीरीज में 3 विकेट लिए और 6.72 का शानदार इकॉनमी रेट बनाए रखा। दूसरी तरफ, तुबा हसन गेंदबाजी रैंकिंग में तीन स्थान की बढ़त के साथ 48वें नंबर पर पहुंच गई हैं। श्रीलंकाई टीम से, कप्तान चामरी अट्टापट्टू अपनी टीम की ऐतिहासिक सीरीज जीत में योगदान देने के बाद 5 स्थान ऊपर चढ़कर 36वें नंबर पर पहुंच गईं। श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम ने साल 2014 के बाद पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय टी20 सीरीज अपने नाम की है, जिसमें इमेशा दुलानी की बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' अवॉर्ड जीता। दाएं हाथ की बल्लेबाज ने 61.50 की औसत से 123 रन बनाए और टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में एक स्थान ऊपर चढ़कर 22वें नंबर पर पहुंच गईं। दुलानी ने 31 जुलाई को शुरुआती मैच में शानदार शुरुआत की और मेजबान टीम को छह विकेट और छह गेंदें शेष रहते हुए 177 रन का लक्ष्य हासिल करने में मदद की।

आखिरकार जॉर्जिना के हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो

10 साल डेट करने के बाद गुपचुप की शादी

लिस्बन (एजेंसी)। फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े सितारों में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब आधिकारिक तौर पर शादीशुदा हो गए हैं। 41 वर्षीय पुर्तगाली सुपरस्टार ने अपनी लंबे समय से पार्टनर रहीं जॉर्जिना रोड्रिगेज को अपना जीवनसाथी बना लिया है। दोनों ने मंगलवार, 11 अगस्त को पुर्तगाल के कास्काइस में एक बेहद निजी सिविल सेरेमनी में शादी की। खास बात यह रही कि इस मौके पर उनके पांच बच्चे भी मौजूद थे।

तीन अक्षरों में दी शादी की खबर

शादी को पूरी तरह निजी रखने वाले रोनाल्डो ने किसी बड़े एलान या भव्य तस्वीरों के बजाय सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को खुशखबरी दी। उन्होंने अपनी और जॉर्जिना की हाथों की तस्वीर शेयर की, जिसमें दोनों की उंगलियों में मैचिंग गोल्ड वेडिंग रिंग नजर आ रहे थे। इस तस्वीर के साथ रोनाल्डो ने सिर्फ 'ष्ट्त' लिखा। और साथ ही दिल भी बनाया। स्पैनिश स्पोर्ट्स डेली मार्का और सऊदी अरब के अखबार गल्फ न्यूज ने भी शादी की पुष्टि की। बताया गया कि यह समारोह बेहद निजी और अंतरंग था तथा इसमें कपल के पांच बच्चे शामिल हुए।

10 साल से ज्यादा समय से साथ हैं

रोनाल्डो और जॉर्जिना का रिश्ता करीब एक दशक पुराना है। दोनों की मुलाकात 2016 में मैड्रिड में हुई थी। उस समय जॉर्जिना एक गुच्ची स्टोर में काम करती थीं। उन्होंने बाद में बताया था कि रोनाल्डो से पहली मुलाकात के दौरान उनके पेट में 'तितलियां उड़ने' जैसा एहसास हुआ था।इसके बाद दोनों का रिश्ता धीरे-धीरे सार्वजनिक हुआ और दोनों ने एक साथ परिवार बसाया। रोनाल्डो के फुटबॉल करियर के स्पेन, इटली, इंग्लैंड और सऊदी अरब तक पहुंचने के दौरान जॉर्जिना लगातार उनके साथ रहीं।

2025 में हुई थी सगाई

शादी से करीब एक साल पहले जॉर्जिना ने अगस्त 2025 में सोशल मीडिया पर अपनी सगाई की जानकारी दी थी। उन्होंने रोनाल्डो के साथ हाथ की तस्वीर शेयर की थी, जिसमें उनकी बड़ी डायमंड रिंग नजर आई थी। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, यस आई डू इन दिस एंड इन ऑल माई लाइव्स।

गुजरात में लौटना चाहते थे हार्दिक... पर जीटी ने बंद किए वापसी के सभी रास्ते!

पांड्या ने ऐसी क्या रख दी थी मांग?

कई टीमों ने हार्दिक में दिखाई दिलचस्पी

मुंबई। हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस के साथ भविष्य एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इसी बीच खबर है कि भारतीय ऑलराउंडर ने अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस में लौटने की कोशिश की थी। गुजरात भी उनकी वापसी के विचार के खिलाफ नहीं था, लेकिन कप्तानी को लेकर रखी गई पांड्या की मांग ने पूरी बातचीत को खत्म कर दिया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक पांड्या ने अपनी पूर्व फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस के साथ वापसी को लेकर बातचीत की थी। पांड्या और गुजरात, दोनों ही इस संभावना के लिए तैयार थे। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि पांड्या ने गुजरात टाइटंस को 2022 में उसके पहले ही सीजन में आईपीएल चैंपियन बनाया था। हालांकि, वापसी के लिए पांड्या की एक अहम शर्त थी। वह चाहते थे कि गुजरात टाइटंस में लौटने के साथ उन्हें दोबारा टीम की कप्तानी भी सौंपी जाए।

कप्तानी की मांग बनी डील ब्रेकर

रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक की कप्तानी की मांग पर गुजरात टाइटंस ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। फ्रेंचाइजी ने मौजूदा कप्तान शुभमन गिल से भी इस संभावित बदलाव को लेकर बात की थी। गिल इस बात के लिए तैयार बताए गए कि फ्रेंचाइजी हार्दिक को वापस ट्रेड कर सकती है। लेकिन जब पांड्या की ओर से कप्तानी को वापसी की शर्त के तौर पर रखा गया, तो गुजरात टाइटंस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 'फ्रेंचाइजी उनके लौटने के पक्ष में थी। उन्होंने अपने कप्तान शुभमन गिल से भी इस बारे में बात की थी और वह भी इसके लिए तैयार थे। लेकिन जब कप्तानी की शर्त सामने आई, तो सभी ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया।'

मुंबई इंडियंस में भी भविष्य पर सवाल

हार्दिक की गुजरात में वापसी की कोशिश ऐसे समय में सामने आई है, जब मुंबई इंडियंस में उनके भविष्य को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का 2026 आईपीएल सीजन निराशाजनक रहा। टीम ने 14 में से सिर्फ चार मैच जीते और अंक तालिका में नौवें स्थान पर रही। पांड्या का मुंबई के प्रशंसकों के साथ रिश्ता भी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने 2021 सीजन के बाद मुंबई का साथ छोड़ा था और 2024 में टीम में वापसी की। वापसी के बाद उन्हें रोहित शर्मा की जगह कप्तान बनाया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुंबई इंडियंस का टीम मैनेजमेंट पांड्या को कप्तान के तौर पर बनाए रखने को लेकर उत्सुक नहीं था। खराब सीजन के बाद टीम में उनकी भूमिका को लेकर भी विचार किया जा रहा था। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स समेत कई फ्रेंचाइजी ने हार्दिक पांड्या को लेकर मुंबई इंडियंस से पूछताछ की है।

पांड्या के प्रवक्ता ने क्या कहा

हालांकि, हार्दिक पांड्या के प्रवक्ता ने इन खबरों पर अलग रुख रखा है। उन्होंने कहा कि ऑलराउंडर ने ट्रांसफर या ट्रेड को लेकर किसी भी फ्रेंचाइजी से सीधे बातचीत नहीं की है। प्रवक्ता के मुताबिक, 'हार्दिक पांड्या ने ट्रांसफर, ट्रेड या किसी अन्य तरीके से किसी भी फ्रेंचाइजी से सीधे बातचीत नहीं की। अगर उनसे कोई संपर्क किया गया है, तो वह मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के जरिए किया गया है।' इस तरह गुजरात टाइटंस में वापसी की चर्चा के बावजूद कप्तानी की शर्त के कारण यह संभावित डील आगे नहीं बढ़ सकी।

संन्यास के बावजूद श्रीलंका दौरे पर क्यों गए अजिंक्य रहाणे

कोलंबो। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे अब मैदान के अंदर नहीं, बल्कि कमेंट्री बॉक्स से टेस्ट क्रिकेट का अनुभव साझा करते नजर आएंगे। रहाणे भारत के आगामी श्रीलंका दौरे पर टेस्ट कमेंट्री में डेब्यू करने वाले हैं। भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज 15 अगस्त से शुरू होगी और इसी सीरीज के साथ रहाणे कमेंट्री की दुनिया में अपनी नई पारी शुरू करेंगे। वह ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स के कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। रहाणे का यह कदम उनके करीब 18 साल लंबे फर्स्ट क्लास करियर के खत्म होने के कुछ ही समय बाद आया है। अपने करियर के बड़े हिस्से में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के मुश्किल माहौल में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। अब 37 साल की उम्र में रहाणे पांच दिन तक चलने वाले टेस्ट मैच को एक खिलाड़ी के बजाय कमेंटेटर के नजरिए से देखेंगे। वह मैच के दौरान रणनीतिक फैसलों, महत्वपूर्ण पलों और मुकाबले की दिशा बदलने वाले घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे। रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 5,077 रन बनाए। उनके नाम 12 शतक और 26 अर्धशतक हैं। अलग-अलग परिस्थितियों में टेस्ट क्रिकेट खेलने और दबाव के बीच प्रदर्शन करने का उनका अनुभव कमेंट्री के दौरान उनके लिए अहम साबित हो सकता है। मैदान पर लंबे समय तक खेलने के बाद अब वह अपने अनुभव के जरिए दर्शकों को टेस्ट क्रिकेट की बारीकियां समझाने की कोशिश करेंगे।

भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए श्रीलंकाई टीम घोषित

कोलंबो। भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट के लिए श्रीलंकाई टीम का एलान हो गया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने मैच के लिए 16 सदस्यीय टीम का एलान किया है। विकेटकीपर-बल्लेबाज निरोसन डिकवेला करीब तीन साल बाद श्रीलंका की टेस्ट टीम में लौटे हैं। 33 वर्षीय डिकवेला ने पिछली बार 2023 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा। वहीं, दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। श्रीलंका के स्क्वॉड में अनकैप्ड ऑफ स्पिनर केशरा नुवांथा और अनकैप्ड टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पसिंदु सूरियाबंदर को भी जगह मिली है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका की भी टीम में वापसी हुई है, जिन्होंने अब तक सिर्फ एक टेस्ट खेला है। वहीं, कुसल मेंडिस और पाथुम निसांका फिलहाल पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं।डिकवेला की वापसी की सबसे बड़ी वजह कुसल मेंडिस का टीम से बाहर होना है। मेंडिस हैमस्ट्रिंग चोट के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। वहीं पाथुम निसांका भी कलाई की सर्जरी से उबर रहे हैं और टीम में नहीं हैं।

बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11 घोषित

डार्विन। ऑस्ट्रेलिया गुरुवार से बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में शुरू होने वाली दो टेस्ट मैच की सीरीज से एक साल में 20 टेस्ट मैच खेलने के अपने व्यस्त कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। इस मैच से 2003 के बाद टेस्ट क्रिकेट की ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वापसी भी होगी। बांग्लादेश का दो दशकों से अधिक समय में ऑस्ट्रेलिया का यह पहला टेस्ट दौरा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग-11 घोषित कर दी है।ऑस्ट्रेलिया का अगले 12 महीने का कार्यक्रम बेहद व्यस्त है। इस दौरान वह 20 टेस्ट मैच खेलेगा, जिसमें विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका, भारत और इंग्लैंड के दौरे भी शामिल हैं। अगर वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचता है तो इन मैच की संख्या 21 हो जाएगी। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा। इसके बाद वह चार टेस्ट मैच के लिए न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया को इसके बाद भारत में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। वह मार्च में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलेगा जो दोनों देशों के बीच टेस्ट मैचों की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा।

भारत की ये झीलें जन्नत से नहीं है कम, इस गर्मी ट्रैवल बकेट लिस्ट में करें शामिल

अगर आप भी इस गर्मी देश की फेमस और खूबसूरत झीलों को देखने का मन बना रहे हैं, तो आज हम आपको देश की कुछ अद्भुत और बेहद खूबसूरत झीलों के बारे में बताने जा रहे हैं। जहां पर जाकर आप अपनी छुट्टियों को खास बना सकते हैं।

गर्मियों के मौसम में लगभर हर कोई ठंडी जगहों या समुद्र तटीय क्षेत्रों पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा इस मौसम में झीलों का नजारा भी देखने लायक होता है। ठंडी-ठंडी हवाओं के बीच झीलों को देखना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे में अगर आप भी इस गर्मी देश की फेमस और खूबसूरत झीलों को देखने का मन बना रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। क्योंकि आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको देश की कुछ अद्भुत और बेहद खूबसूरत झीलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर जाकर आप अपनी छुट्टियों को खास बना सकते हैं।

बड़ी लेक

राजस्थान के माउंट आबू में मीठे पानी की एक विशाल झील है। इसको बड़ी लेक के नाम से भी जाना जाता है। गर्मियों में यहां का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। बताया जाता है कि बड़ी लेक को खुद भगवान ने बनाया था। हर साल यहां पर बड़ी संख्या में लोग अपनी छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए आते हैं।

नैनी झील

नैनीताल के लोगों के लिए नैनी झील काफी ज्यादा फेमस है। नैनी झील को नैनीताल झील के नाम से भी जाना जाता है। नैनी झील में आप नौकायन यानी की नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं। हर साल यहां पर देशी और विदेशी पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं।

हुसैन सागर झील

वहीं हैदराबाद में हुसैन सागर झील है, जोकि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। बताया जाता है कि इस हुसैन झील के तट पर गोलकुंडा और मुगलों के बीच संधि हुई थी। इसके साथ ही इस लेक में बुद्ध देवता की विशाल मूर्ति है। गर्मियों में हुसैन सागर झील का नजारा देखने लायक होता है।

लोकटक झील

लोकटक झील मणिपुर में है और यह झील पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा फेमस है। इस झील को फ्लोटिंग झील के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि लोकटक झील दुनिया की इकलौती ऐसी लेक है, जोकि तैरती हुई दिखाई देती है। ऐसे में अगर आप गर्मियों में मणिपुर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको एक बार लोकटक झील देखने जरूर जाना चाहिए।

टारसर झील

बता दें कि जम्मू-कश्मीर में टारसर झील मौजूद है, जोकि काफी ज्यादा खूबसूरत है। यह झील पर्वतीय इलाके में जमीन से करीब 3,795 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। टारसर झील के आसपास बड़े-बड़े पहाड़ हैं, जोकि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं।

प्रकृति, इतिहास और आध्यात्म का अद्भुत संगम है शिवपुरी

शिवपुरी का नाम भगवान शिव के नाम पर पड़ा है। यह नगर कभी नरवर रियासत का हिस्सा था और बाद में ग्वालियर राज्य के अधीन आ गया। सिंधिया राजवंश ने यहाँ कई महलों, उद्यानों और स्मारकों का निर्माण करवाया, जो आज भी उसकी राजसी भव्यता की गवाही देते हैं।

शिवपुरी मध्य प्रदेश का एक सुरम्य और ऐतिहासिक नगर है, जो अपनी हरियाली, प्राचीन स्मारकों, राजसी विरासत और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यह नगर एक समय में सिंधिया राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है और आज यह पर्यटकों के लिए एक शांत, सुंदर और विविध अनुभव प्रदान करता है।

शिवपुरी का ऐतिहासिक परिचय

शिवपुरी का नाम भगवान शिव के नाम पर पड़ा है। यह नगर कभी नरवर रियासत का हिस्सा था और बाद में ग्वालियर राज्य के अधीन आ गया। सिंधिया राजवंश ने यहाँ कई महलों, उद्यानों और स्मारकों का निर्माण करवाया, जो आज भी उसकी राजसी भव्यता की गवाही देते हैं।

शिवपुरी के प्रमुख दर्शनीय स्थल

1. माधव राष्ट्रीय उद्यान

शिवपुरी का सबसे प्रसिद्ध स्थल। यह राष्ट्रीय उद्यान कभी सिंधिया राजाओं का शिकार क्षेत्र हुआ करता था। अब यह बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ, और अनेक पक्षियों का निवास स्थान है। यह प्रकृति प्रेमियों और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर्स के लिए स्वर्ग है।

2. सिंधिया की छतरियाँ

सिंधिया राजाओं और रानियों की याद में बने ये संगमरमर के स्मारक भारतीय और मुगल वास्तुकला के सुंदर मिश्रण का उदाहरण हैं। यहाँ की कलाकृति, मेहराबें और जालीदार खिड़कियाँ देखने योग्य हैं।

3. माधव विलास महल

यह एक भव्य शाही महल है, जहाँ सिंधिया परिवार गर्मियों में रहा करता था। ऊँचाई पर स्थित यह महल अपने बगीचों, झरोखों और शाही वातावरण के लिए प्रसिद्ध है।

4. सागर तालाब और भदैया कुंड

शिवपुरी के यह जल स्रोत प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ स्थानीय लोगों की आस्था से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ बैठकर आप शांति का अनुभव कर सकते हैं।

5. नरवर किला

शिवपुरी से लगभग 40 किमी दूर स्थित यह प्राचीन किला 10वीं शताब्दी में बना था और चंदेल, परमार, तोमर, और मुगलों के अधीन रहा। किले से आसपास का मनोरम दृश्य दिखाई देता है।

धार्मिक स्थल

सिद्धेश्वर महादेव मंदिर – एक प्राचीन शिव मंदिर जो स्थानीय श्रद्धालुओं के बीच अत्यंत पूजनीय है।

छत्री मंदिर परिसर – यहाँ भगवान विष्णु और अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियाँ स्थापत्य कला का अनोखा उदाहरण हैं।

क्या करें?

वन सफारी – माधव राष्ट्रीय उद्यान में सुबह या शाम की सफारी जरूर लें।

फोटोग्राफी – प्रकृति, इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम आपको कैमरे से दूर नहीं रहने देगा।

स्थानीय भोजन – यहाँ का पारंपरिक मालवी और बुंदेली खाना जरूर चखें।

कैसे पहुँचे?

निकटतम रेलवे स्टेशन- शिवपुरी रेलवे स्टेशन, ग्वालियर (110 किमी)

निकटतम हवाई अड्डा- ग्वालियर

सड़क मार्ग- ग्वालियर, झाँसी, भोपाल और इंदौर से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है

ठहरने की व्यवस्था

शिवपुरी में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित रिसॉर्ट्स, लॉज और कई निजी होटल उपलब्ध हैं। यदि आप प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान के पास रिसॉर्ट एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं।

यात्रा का सर्वोत्तम समय

अक्टूबर से मार्च के बीच का मौसम शिवपुरी घूमने के लिए सबसे उपयुक्त है। इस समय तापमान सुखद होता है और वन्यजीव भी अधिक दिखते हैं।

शिवपुरी एक ऐसा स्थल है जहाँ इतिहास के पदचिन्ह, राजसी भव्यता, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति— सब एक साथ मिलते हैं। यह पर्यटन के शोरगुल से दूर, आत्मिक और सुकून भरी यात्रा के लिए आदर्श स्थल है। यदि आप मध्य प्रदेश की अनदेखी विरासत को महसूस करना चाहते हैं, तो शिवपुरी की यात्रा जरूर करें।

खूबसूरत तैमारा घाटी का खौफनाक रहस्य, यहां आते ही बदल जाता है मोबाइल का वक्त

झारखंड की खूबसूरत जगहों के बीच तैमारा घाटी के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। तैमारा घाटी झारखंड में %मौत का हाइवे% के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में आज हम आपको तैमारा घाटी की डरावनी कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। झारखंड भारत का एक प्रमुख और खूबसूरत राज्य है। यह राज्य साल 2000 में बिहार से अलग होकर देश का 28वां राज्य बना था। आज झारखंड पूरे भारत का एक खनिज समृद्ध राज्य माना जाता है। झारखंड घने जंगलों, कोयला खदानों और बेहतरीन पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। झारखंड की पतरानू घाटी, हुंडरू, टैगोर हिल और दशम वॉटरफॉल, नेतरहाट और तोपचांची झील जैसी खूबसूरत जगहों के बारे में हर कोई जानता है।

इन खूबसूरत जगहों के बीच तैमारा घाटी के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। तैमारा घाटी झारखंड में %मौत का हाइवे% के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको तैमारा घाटी की डरावनी कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं।

तैमारा घाटी

तैमारा घाटी एक डरावनी जगह मानी जाती है, जोकि रांची-जमशेदपुर हाईवे यानी एनएच-33 पर है। यह जगह राजधानी रांची से करीब 30 किमी की दूरी पर है। हाइवे पर होने के कारण तैमारा घाटी को %मौत का हाइवे% के नाम से भी जानी जाती है। यह हाइवे घने जंगलों के बीच में है, जिसकी वजह से यह काफी डरावना लगता है।

तैमारा घाटी की घटनाएं

तैमारा घाटी की एक नहीं बल्कि कई घटनाएं प्रचलित हैं। यह घाटी देखने में तो काफी मनमोहक लगती है। लेकिन यह घाटी कई मौतों की गवाह भी बन चुकी है। बताया जाता है कि इस घाटी गुजरने पर टाइम और तारीख अपने आप बदल जाती है।

तैमारा घाटी को लेकर एक अन्य कहानी है कि जंगलों के बीच से जब गाड़ी गुजरती है, तो उस गाड़ी की स्पीड मीटर खुद ब खुद बदल जाती है। वहीं माना जाता है कि रात के समय इस घाटी से अजीबो-गरीब आवाजें आती रहती हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि डर के कारण लोग रात में अकेले इस घाटी से गुजरना नहीं चाहते हैं।

तैमारा घाटी की डरावनी कहानियां

इस घाटी की सबसे डरावनी कहानियों में फेमस कहानी मोबाइल में डेट और समय का बदल जाना है। कई लोगों का इस घाटी के बारे में मानना है कि जब कोई यहां से गुजरता है तो उसके मोबाइल में साल, डेट और समय अपने आप बदल जाता है।

ऐसा होने के पीछे लोग कुछ और कहानी भी बताते हैं। लोगों का मानना है कि तैमारा घाटी से कुछ ही दूरी पर मैग्नेटाइज्ड रॉक है। जिसकी वजह से यह समस्या होती है। वहीं एक अन्य कारण यह भी है कि इसी घाटी से कर्क रेखा गुजरती है, जिस वजह से यह समस्या होती है।

तैमारा घाटी घूमने जाते हैं पर्यटक

बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची से करीब 30 किमी दूर स्थित तैमारा घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां पर भीषण गर्मी में भी ठंडी-ठंडी हवाएं चलती हैं। ऐसे में पर्यटक भी तैमारा घाटी घूमने के लिए पहुंचते हैं। मानसून के समय पर्यटक दूर-दूर से यहां पर लॉन्ग ड्राइव के लिए पहुंचते हैं। मानसून में इस घाटी की खूबसूरती देखने लायक होती है।

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

मणिपुर के कांगपोकपी में नागा गांव पर हमला, नौ मकान जलाए

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में हथियारबंद बदमाशों ने एक नागा गांव पर हमला कर कई मकानों में आग लगा दी। सूत्रों के अनुसार, लियांगमाई नागा समुदाय के कम से कम नौ मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गए। घटना मंगलवार रात करीब 9-30 बजे टोकपा लियांगमाई गांव में हुई। टोकपा लियांगमाई गांव महिका और लोअर थानंबा गांवों के बीच स्थित है। देर रात हुए हमले में नौ मकानों के पूरी तरह जलने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, हमले के पीछे की परिस्थितियों और इसमें शामिल लोगों की पहचान तत्काल स्पष्ट नहीं हो सकी है। घटना के बाद गांव में भय और चिंता का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की तत्काल जांच कराने और क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। बुधवार सुबह तक कांगपोकपी जिला प्रशासन, मणिपुर पुलिस या सुरक्षा बलों की ओर से घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। यह भी स्पष्ट नहीं है कि हमले में किसी व्यक्ति की मौत या घायल होने की सूचना है या नहीं। मणिपुर के कई हिस्सों में पहले से जारी तनाव के बीच इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने बेंगलुरु जेल में छापा मारा, रेवन्ना व दो कैदियों के पास मिले फोन

बेंगलुरु (एजेंसी)। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने बेंगलुरु स्थित परप्पना अग्रहारा जेल में छापेमारी की। छापेमारी में जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना और प्रताप राय नाम के एक अन्य कैदी के पास फोन मिले हैं। दोनों के खिलाफ परप्पना अग्रहारा जेल में प्रिजन्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह धारा जेल के अंदर या बाहर गैर-कानूनी सामान लाने, बिना इजाजत कैदियों से बात करने या इन नियमों को तोड़ने में मदद करने पर सजा का प्रावधान है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच अधिकारी नोटिस भेजने और आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले वे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं और और जानकारी जुटा रहे हैं। डीजीपी जेल ने बताया कि मंगलवार दोपहर सीसीबी ने सभी हाई-प्रोफाइल कैदियों के यहां छापेमारी की। प्रज्वल रेवन्ना के पास से एक एंड्रॉयड फोन ज़ब्त किया है। डीआईजी (साउथ) की रिपोर्ट पर संबंधित असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है और बैंगलोर सेंट्रल जेल के एसपी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। इस घटना की विस्तृत जांच की जा रही है।

अमेरिकी वीज़ा के लिए फर्जीवाड़ा : आंध्र प्रदेश का युवक गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिकी दूतावास की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने आंध्र प्रदेश के 25 वर्षीय युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। युवक पर गैर-आप्रवासी वीजा के लिए आवेदन करते समय फर्जी दस्तावेज जमा करने का आरोप है। घटना 7 अगस्त को नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में हुई, जहाँ युवक वीज़ा इंटरव्यू के लिए पहुंचा था। आरोपी ने अपनी शैक्षिक योग्यता के रूप में राजस्थान के एक विश्वविद्यालय से कंप्यूटर्स में बैचलर ऑफ कॉमर्स की फर्जी डिग्री पेश की। इतना ही नहीं आरोपी ने 35,000 रुपये मासिक वेतन दिखाने वाला एक कंपनी का अप्रेजल पत्र और ढाई साल के अनुभव का दावा करने वाला अनुभव प्रमाण पत्र पेश किया। वित्तीय स्थिति को मजबूत दिखाने के लिए, युवक ने 1.2 करोड़ रुपये की संपत्ति दर्शाने वाला नेटवर्थ प्रमाण पत्र और बैंक खातों में 45 व 50 लाख रुपये का बैलेंस दिखाया। हालाँकि, इंटरव्यू के दौरान पूछताछ में युवक टूट गया और स्वीकार किया कि कभी विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं की और सभी शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी थे। युवक ने बताया कि ये फर्जी दस्तावेज विजयवाड़ा के वीजा एजेंट नितिन ने उपलब्ध कराए थे। युवक ने माना कि मैंने केवल दो-ढाई महीने ही काम किया था और रोजगार संबंधी दस्तावेज उसके चाचा की कंपनी ने दिए थे।

राम मंदिर चढ़ावा विवाद : सपा सांसद का भाजपा पर बड़ा हमला, श्रद्धालु घटने का दावा

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर तीखा हमला कर दावा किया है कि इस प्रकरण में कुछ छोटे लोगों को गिरफ्तार कर बड़ी मछली को बचाया गया है। उन्होंने मोदी सरकार से इस पूरे मामले पर सदन में जवाब देने की मांग की है।

सांसद प्रसाद ने अयोध्या की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले अयोध्या में रोजाना लाखों श्रद्धालु पहुंचते थे और बड़ी संख्या में सोने, चांदी व नकदी का चढ़ावा चढ़ाया जाता था। उनके अनुसार, अब श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी आई है और रोजाना 10 हजार तक की भीड़ भी नहीं पहुंच रही है। सांसद प्रसाद ने दावा किया कि पहले जहां लाखों रुपये का चढ़ावा आता था, वहीं अब 5, 11, 21 और 51 रुपये जैसी छोटी रकम ही चढ़ावे में आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अयोध्या की मर्यादा को तोड़ने और कलंकित करने का काम किया है। उन्होंने चंदा चोरी प्रकरण की निष्पक्ष जांच और इसके पीछे के दोषियों को सामने लाने की मांग भी की। वहीं, राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पद के लिए साक्षात्कार जारी हैं। उम्मीदवारों से इंटरव्यू से पहले करीब तीन दर्जन सवालों वाला ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरवाया गया। इन सवालों में प्रशासनिक अनुभव के साथ-साथ धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े प्रश्न शामिल थे। उम्मीदवारों से पूछा गया कि क्या वे शिक्षा रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं या मांसाहारी, और क्या वे शराब का सेवन करते हैं। हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था को लेकर भी सवाल किए। साक्षात्कार में प्रशासनिक क्षमता, नेतृत्व कौशल, धार्मिक-सामाजिक जुड़ाव और मंदिर के भविष्य को लेकर उनके दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया गया है। मंगलवार को 18 में से 8 उम्मीदवारों का आमने-सामने साक्षात्कार हुआ, जिसमें चार पूर्व आईएएस अधिकारी शामिल थे।

पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का किया विमोचन

-कार्यक्रम में शॉर्टकट के दौर में युवाओं को सावधान रहने का दिया संदेश

नई दिल्ली(एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रामनाथ कोविंद की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में एक मिसाल कायम की है। पद छोड़ने के बाद भी रामनाथ कोविंद देश के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वह 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर बनी जेपीसी के अध्यक्ष भी हैं। पीएम मोदी ने कोविंद की आत्मकथा 'भारतीय गणतंत्र की विजय- मेरा जीवन, मेरा संघर्ष' का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि देश की नई पीढ़ी को इस किताब को पढ़ना चाहिए और कोविंद के अनुभवों से सीखना चाहिए।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि किताब का शीर्षक बिल्कुल सही है। इसमें रामनाथ कोविंद के व्यक्तिगत जीवन और संघर्षों की कहानी है, लेकिन उनकी सफलता सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि भारतीय गणतंत्र और लोकतंत्र की जीत है। पीएम ने कार्यक्रम में एक वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि जब वे प्रधानमंत्री के तौर पर राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने जाते थे। तब प्रोटोकॉल के बावजूद रामनाथ कोविंद अक्सर औपचारिकताओं से हटकर उनसे बातचीत करते थे। इतना ही नहीं, वह प्रधानमंत्री को विदा करने के लिए खुद कार के दरवाजे तक आते थे। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने कई बार पूर्व राष्ट्रपति से ऐसा न करने को कहा, लेकिन उन्होंने अपनी यह विनम्रता कभी नहीं छोड़ी।

पीएम मोदी ने रामनाथ कोविंद के गांव परौंख जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद जब कोविंद अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने अपने शिक्षकों के पैर छुए, गांव की मिट्टी को नमन किया और वहां के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोविंद का यह भावुक अंदाज पूरे देश ने देखा उनके व्यवहार ने दुनिया के सामने भारत के संस्कार और सांस्कृतिक मूल्यों की ऐसी तस्वीर पेश की, जिस पर हर भारतीय को गर्व होता है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जेन-जी को भी खास संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज के सोशल मीडिया के जमाने में कई इन्फ्लुएंसर्स युवाओं को आकर्षित करते हैं, लेकिन इस शॉर्टकट के दौर में भी युवाओं को सावधान रहना चाहिए। पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन पर लिखी एक लाइन का उदाहरण देते हुए कहा रेलवे स्टेशन पर भी लोग ब्रिज से जाने की बजाय पटरी पार करने की कोशिश करते हैं। उन्होने कहा कि यह गलत शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने युवाओं से कहा कि अगर वे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और दूसरों के अनुभवों से सीखना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी पसंद के लोगों की ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए।

दो किसानों को ले गए थे बांग्लादेशी- फ्लैग मीटिंग के बाद हुई रिहाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर उस समय अचानक तनाव गहरा गया जब बांग्लादेशी ग्रामीणों ने सीमा पार कर दो भारतीय किसानों का अपहरण कर लिया। यह घटना पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के सीमावर्ती इलाके में घटी, जहां खेत में काम कर रहे दो भारतीय किसानों को जबरन खींचकर बांग्लादेश ले जाया गया। हालांकि, दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के बीच तत्काल हुई उच्चस्तरीय फ्लैग मीटिंग के बाद स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया और आपसी सहमति से सभी नागरिकों को सुरक्षित रिहा करा लिया गया। विवाद की पूरी शुरुआत मंगलवार सुबह बांग्लादेश के मेहेरपुर स्थित इच्छाखाली बॉर्डर के पास हुई। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, अब्दुल मन्नान नामक एक बांग्लादेशी किसान सीमावर्ती क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन कर फसल पर कीटनाशक छिड़क रहा था, जिसके चलते भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने उसे हिरासत में ले लिया था। इस कार्रवाई से आक्रोशित होकर दर्जनों बांग्लादेशी ग्रामीण भड़क उठे और सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने खेतों में काम कर रहे सचिन कर्मकार और नारायण देब नामक दो भारतीय किसानों को बंधक बना लिया और उन्हें बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के हवाले कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी गई और तनाव को कम करने के लिए मंगलवार दोपहर इच्छाखाली सीमा पर जीरो लाइन पर दोनों देशों के बलों के बीच फ्लैग मीटिंग बुलाई गई। लंबी बातचीत के बाद सहमति बनी, जिसके तहत बीएसएफ ने हिरासत में लिए गए बांग्लादेशी नागरिक को बीजीबी को सौंप दिया, और इसके बदले में बांग्लादेशी ग्रामीणों द्वारा उठाए गए दोनों भारतीय किसानों को सुरक्षित वापस भारत के हवाले कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि सीमा पार से भारतीय नागरिकों के अपहरण की इस क्षेत्र में हाल के दिनों में यह दूसरी बड़ी घटना है।

गटर जनरेशन कहकर फंसी कंगना! 21 को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी विवादित बयानों के चलते एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों और जेन जेड के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में उत्तर प्रदेश के आगरा की एक विशेष अदालत ने उनके खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। यह याचिका जंतर-मंतर पर प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों, उनके माता-पिता और युवाओं पर की गई टिप्पणियों के संबंध में दाखिल की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है, जिस दिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।

अदालत में याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने जानकारी दी कि सांसद कंगना रनौत के खिलाफ एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में वाद दायर किया गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि जब छात्र और युवा अपनी मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तब अभिनेत्री ने उन्हें गटर जनरेशन या गटर छाप करार दिया और उनके माता-पिता के खिलाफ भी अपमानजनक बातें कहीं। वकील ने इसे देश के युवाओं और छात्रों का सीधा अपमान बताया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है, जिस दिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। याचिकाकर्ता ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि स्थानीय अदालत से इस मामले में राहत नहीं मिलती है, तो वह इस कानूनी लड़ाई को उच्च न्यायालय और जरूरत पड़ने पर देश के उच्चतम न्यायालय तक लेकर जाएंगे।

राहुल गांधी बोले- लेक्चर नहीं सुनना, पैलेट गन का आदेश दिया तो शाह इस्तीफा दें

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सदन में चर्चा के आह्वान पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई लेक्चर नहीं सुनना है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश अमित शाह ने दिया था तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, कि देश की युवा पीढ़ी अमित शाह के काल्पनिक भाषण सुनने में दिलचस्पी नहीं रखती। उन्होंने सरकार से सीधा सवाल करते हुए पूछा कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश आखिर किसने दिया था। राहुल गांधी ने सवाल किया कि किसके आदेश पर एक छात्र को कथित तौर पर अंधा कर दिया गया और दूसरे छात्र को गोली मारी गई। उन्होंने यह भी पूछा कि छात्रों को कीलों वाली लाठियों से पीटने का आदेश किसने दिया था।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्हें और युवाओं को गृह मंत्री की सफाई या तर्क नहीं चाहिए। उनकी मांग है कि सरकार पहले यह स्पष्ट करे कि छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग का आदेश किस स्तर से दिया गया था। उन्होंने कहा कि जब तक इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, तब तक किसी तरह का लेक्चर या सामान्य चर्चा स्वीकार नहीं की जाएगी। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि पैलेट गन चलाने का आदेश अमित शाह ने दिया था तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।

स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट, रातभर चलाई जा रही सघन चेकिंग

नई दिल्ली (एजेंसी)। स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा है। सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में देर रात मेगा सुरक्षा अभियान चलाया। रात 11 बजे से 2 बजे तक दिल्ली के तमाम जिलों में गश्त के साथ सघन चेकिंग की गई। द्वारका मोड़ पर पुलिसकर्मियों ने पूरी सतर्कता के साथ आधी रात को पेट्रोलिंग की। अधिकारियों ने गाड़ियों की सघन जांच की और हर गुजरने वाली कार की अंदर-बाहर से अच्छी तरह तलाशी ली गई। सिर्फ सुरक्षा जांच में पास होने वाली गाड़ियों को ही आगे जाने की इजाजत दी गई।

इसी तरह उत्तम नगर में पुलिस टीमों ने आधी रात को सघन चेकिंग अभियान चलाया। इलाके की मुख्य सड़कों से गुजरने वाली हर गाड़ी को रोका गया और उसकी बारीकी से जांच की गई। इस निगरानी का मकसद पूरे शहर में पूरी सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना है। सीलमपुर इलाके में भी दिल्ली पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान, संदिग्ध वाहनों और लोगों पर नजर रखी गई। सुरक्षा अभियान के तहत पुलिसकर्मियों को स्थानों पर तैनात किया गया। वहीं, पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पीकेट लगाकर आने-जाने वाले वाहनों की जांच की। इस दौरान संदिग्ध वाहनों और लोगों पर विशेष नजर रखी गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए इस तरह के अभियान जारी रहेंगे।

मुंबई के कुर्ला और घाटकोपर में जमीन धंसने से अब तक 6 की मौत

कई लोगों के दबे होने की आशंका

मुंबई (एजेंसी)। मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर तबाही मचाई है। बुधवार तड़के भारी बारिश के कारण शहर के अलग-अलग इलाकों में भूस्खलन और घरों के ढहने की दुखद घटनाएं सामने आई हैं। कुर्ला के चिराग नगर और घाटकोपर के अशोकनगर इलाके में पहाड़ का हिस्सा गिरने और चॉल ढहने की चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई है, वहीं मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। हादसा बुधवार सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच हुआ, जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक हुए भूस्खलन के कारण गौसिया चॉल समेत अन्य मकान मलबे में तब्दील हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, अग्निशमन दल, पुलिस, एंबुलेंस और राहत एवं बचाव टीमों ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। मलबे को हटाने के लिए मशीनों और उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है और घायलों को निकालने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच चुके हैं ताकि राहत कार्यों की निगरानी की जा सके और पीड़ितों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। हर साल मानसून के दौरान मुंबई में इस तरह के हादसे चिंता का विषय बनते हैं। पहाड़ों के ढलान और असुरक्षित इलाकों में बनी चॉल व अस्थाई मकान बारिश में सबसे ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। प्रशासन और बचाव एजेंसियां समय-समय पर लोगों को ऐसे क्षेत्रों को खाली करने की चेतावनी देती रही हैं और सतर्क रहने की अपील करती हैं, लेकिन इसके बावजूद कई लोग इन असुरक्षित घरों में रहने को मजबूर हैं। ये निर्माण न केवल भौगोलिक रूप से जोखिम भरे क्षेत्रों में होते हैं, बल्कि बारिश का दबाव झेलने में भी असमर्थ साबित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी जानलेवा घटनाएं होती हैं। इस बीच, मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों-जैसे ठाणे, पालघर और रायगढ़-के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शहर में मानसून की बारिश का सिलसिला अभी थमा नहीं है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश ने पहले ही जलभराव की समस्याएं पैदा कर दी हैं, और अब इन भूस्खलनों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। फिलहाल पूरा ध्यान मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने पर केंद्रित है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों और जर्जर मकानों के पास जाने से बचें और अत्यधिक सतर्कता बरतें।

फैल रहा वायब्रियो वल्निफिकस बैक्टीरिया, पाया जाता है समुद्री और खारे पानी में

-विशेषज्ञों ने दी चेतावनी- बैक्टीरिया गंभीर घाव का कारण बनकर हो सकता है जानलेवा

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका के कुछ तटीय इलाकों में इन दिनों समुद्र किनारे जाने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। यहां वायब्रियो वल्निफिकस नामक एक खतरनाक बैक्टीरिया, जो गर्म समुद्री और खारे पानी में पाया जाता है। हाल के महीनों में इसके संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अमेरिका के लुइसियाना राज्य में इस साल अब तक नौ लोग इसकी चपेट में आए हैं, जिनमें सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पांच लोगों की मौत हो चुकी है। गंभीर मामलों में यह बैक्टीरिया शरीर के ऊतकों को तेजी से नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसे आम बोलचाल में फ्लेश-ईटिंग बैक्टीरिया यानी मांस को नुकसान पहुंचाने वाला बैक्टीरिया कहा जाता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक वायब्रियो वल्निफिकस प्राकृतिक रूप से गर्म समुद्री और खारे-मीठे पानी के मिश्रित क्षेत्रों में पाया जाता है। संक्रमण मुख्य रूप से दो तरीकों से फैलता है। पहला यदि किसी व्यक्ति के शरीर पर कट, घाव या त्वचा पर चोट हो और वह दूषित समुद्री पानी के संपर्क में आए। दूसरा- कच्चे या अधपके समुद्री भोजन, विशेषकर ऑयस्टर जैसी शेलफिश के सेवन से। ज्यादातर संक्रमण सामान्य हो सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह बैक्टीरिया रक्त संक्रमण और गंभीर घाव का कारण बनकर जानलेवा भी साबित हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्री पानी के संपर्क के बाद यदि घाव के आसपास लालिमा, सूजन, तेज दर्द, त्वचा का रंग बदलना, बुखार, ठंड लगना या त्वचा पर छाले बनने जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टरों की मदद लें। गंभीर स्थिति में ऊतक काले पड़ने लगते हैं और संक्रमण तेजी से फैल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के संदर्भ में विशेषज्ञों का कहना है कि देश की लंबी समुद्री तटरेखा और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की जरुरत है। मछुआरे, समुद्री खाद्य पदार्थों से जुड़े कर्मचारी और नियमित रूप से समुद्र में जाने वाले लोग इस बैक्टीरिया के संपर्क में आने की आशंका वाले समूहों में शामिल हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल भारत में अमेरिका जैसी व्यापक स्थिति या किसी बड़े प्रकोप की पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि घबराने की जरुरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है।

यदि शरीर पर कोई खुला घाव हो तो समुद्र या खारे पानी में जाने से बचें। यदि घाव समुद्री पानी के संपर्क में आ जाए तो उसे तुरंत साबुन और स्वच्छ पानी से अच्छी तरह धोएं। साथ ही समुद्री भोजन, विशेष रूप से शेलफिश, को हमेशा अच्छी तरह पकाकर ही खाएं। विशेषज्ञों के मुताबिक गर्म मौसम में यह बैक्टीरिया ज्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए बारिश और गर्मी में तटीय क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतना ही सबसे प्रभावी बचाव है।

लाल किले पर 80 साल बाद सुनाई देगा वंदे मातरम: क्यों बदला इतिहास और क्या है नया कानून

नई दिल्ली (एजेंसी)। इस बार 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से नया इतिहास रचा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन से ठीक पहले, पूरे लाल किले में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की गूंज सुनाई देगी। आजादी के बाद पहला मौका है जब स्वतंत्रता दिवस के आधिकारिक और मुख्य प्रोटोकॉल में वंदे मातरम को इतना विशिष्ट स्थान मिला है। अब तक, कड़े सैन्य और राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत ध्वजारोहण समारोह में केवल राष्ट्रगान जन गण मन को प्राथमिकता मिलती थी। लेकिन रक्षा मंत्रालय के नए और ऐतिहासिक प्रोटोकॉल बदलावों के तहत, इस बार पूरे वंदे मातरम के ओजस्वी स्वरों से देश के स्वाभिमान का एक नया अध्याय शुरू होगा।

इस बदलाव की जड़ें लंबे समय से चली आ रही बहस में निहित हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इस कविता के शुरुआती दो पद मातृभूमि की सामान्य स्तुति करते हैं, लेकिन बाद के पदों में हिंदू देवियों, विशेषकर दुर्गा, का स्पष्ट उल्लेख और उनसे जुड़ी कल्पनाएं हैं। इन्हीं धार्मिक संदर्भों पर मुस्लिम लीग और अन्य समूहों की आपत्तियां थीं, इसकारण 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर जैसी हस्तियों की सलाह पर बाद के पदों को हटाने और सार्वजनिक राजनीतिक मंचों के लिए केवल शुरुआती दो पदों का इस्तेमाल करने का फैसला किया था। भारत के गणतंत्र बनने पर, 1950 में संविधान सभा ने जन गण मन को आधिकारिक राष्ट्रगान और वंदे मातरम के शुरुआती दो पदों को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। इस प्रकार उन्हें समान सम्मान दिया गया, लेकिन सरकारी प्रोटोकॉल के लिए धर्मनिरपेक्ष संतुलन भी बनाए रखा गया।

अब संसद ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2026 पारित किया है, इसके तहत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर कानूनी दर्जा मिला है। यह नया कानून, जो पिछले महीने जुलाई में ही पास किया गया, जान-बूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डालने या इसका अनादर करने को दंडनीय अपराध बनाता है। यह संशोधन 1971 के उस अधिनियम में किया गया है जो पहले केवल राष्ट्रगान से संबंधित था। इस ऐतिहासिक बदलाव के तहत, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में, राष्ट्रगान से ठीक पहले लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम बजाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस अवसर पर भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बड़ा ध्वज भी लेकर उड़ेगा, जो इस आयोजन की भव्यता को और बढ़ाएगा।

संक्षिप्त समाचार

सर्जनों को रिश्वत देने के मामले में भारतीय मूल के सीएफओ को जेल, आखिर क्या है पूरा मामला

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने स्पाइनल इंप्लांट कंपनी के भारतीय मूल के मुख्य वित्तीय अधिकारी को सर्जनों को रिश्वत देने के मामले में चार महीने जेल की सजा सुनाई है। दरअसल सीएफओ ने कंपनी के उत्पादों का इस्तेमाल करने के लिए सर्जनों को रिश्वत देने की कोशिश की। अधिकारियों ने बताया कि सर्जनों को यह रिश्वत फर्जी परामर्श शुल्क के रूप में दी गई थी। जेल की सजा पूरी करने के बाद कैम्ब्रिज निवासी 41 वर्षीय आदित्य हुमाड को एक साल तक निगरानी में रहना होगा और उन पर 9,500 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है। हुमाड ने एंटी-किकबैक कानून के उल्लंघन की साजिश रचने के आरोप में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। हुमाड पर सितंबर 2021 में स्पाइन फ्रंटियर नामक कंपनी के संस्थापक, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंग्सले आर. चिन के साथ आरोप लगाए गए थे। मैसाचुसेट्स जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि हुमाड ने उन सर्जनों को 5,40,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक की रिश्वत देने और दिलाने की साजिश रची। यह रकम ऐसे फर्जी परामर्श शुल्क के रूप में दी गई, जिनके लिए सर्जनों ने वास्तव में कोई काम नहीं किया था। अधिकारियों के अनुसार, हुमाड ने सर्जनों को कंपनी के उत्पादों का इस्तेमाल करने के लिए रिश्वत देने की साजिश रची। इसके बदले कंपनी को इन सर्जनों द्वारा की गई सर्जरी से लाखों डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ। अमेरिकी अटॉर्नी लीह बी. फोले ने कहा कि हुमाड को जटिल रीढ़ की सर्जरी में चिकित्सकों को कंपनी के उत्पादों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से रिश्वत देने की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है।

तुर्किये में कुर्द लड़ाकों को मिलेगी सशर्त माफी, संसद से मिली मंजूरी; कानून कब कैसे लागू होगा

अंकारा, एजेंसी। तुर्किये की संसद ने कुर्द लड़ाकों को सशर्त माफ करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये कानून तभी लागू होगा जब तुर्किये के अधिकारी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) के पूरी तरह हथियार डालने की पुष्टि करेंगे। पीकेके ने पिछले साल अपनी दशकों पुरानी सशस्त्र मुहिम खत्म करने और खुद को भंग करने की घोषणा की थी। यह निर्णय उसके जेल में बंद नेता अब्दुल्ला ओकलान के आह्वान पर लिया गया। यह कदम हजारों लोगों की जान लेने वाले संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में है। इससे तुर्किये-इराकी संबंध मजबूत हो सकते हैं। यह सीरियाई सरकार के उन क्षेत्रों को एकीकृत करने के प्रयासों का भी समर्थन करेगा, जो कुर्द-नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज के नियंत्रण में थे।

'हम भी मांगेंगे हर्जाना': ईरान की मुआवजे की मांग पर ट्रंप का नया दांव, बोले- अब हर बातचीत में होगा मुद्दा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से उन लोगों के लिए मुआवजे की मांग की है, जो तेहरान से जुड़े संघर्षों में मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच भविष्य में होने वाली किसी भी बातचीत में यह मुद्दा शामिल किया जाएगा। ट्रंप की यह मांग उस दावे के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के प्रतिनिधियों ने पांच महीने के सैन्य संघर्ष के दौरान ईरान को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की है। ट्रंप ने एक पोस्ट में ईरान की इस मांग को 'दिलचस्प विचार' बताया। उन्होंने कहा कि वह भी तेहरान से इसी तरह की मांग कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ''मैं भी ईरान से उन सभी लोगों के लिए मुआवजे की मांग कर रहा हूं, जिन्हें उसने अपने सड़क किनारे बमों और कई संघर्षों में मारा और गंभीर रूप से घायल किया है, जिनके लिए वह मशहूर है।'' ट्रंप ने उन संघर्षों का भी जिक्र किया, जिनमें ईरानी सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी शामिल थे। उन्होंने यूएसएस कोल पर मारे गए लोगों के परिवारों के लिए भी मुआवजे की मांग की। इसके अलावा उन्होंने युद्ध में मारे गए हजारों अन्य लोगों के परिवारों का भी जिक्र किया। ट्रंप ने पिछले पांच दशकों के दौरान ईरान में प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए भी मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा, ''इसके अलावा, पिछले 50 वर्षों में ईरान द्वारा मारे गए सैकड़ों हजारों निर्दोष प्रदर्शनकारियों के परिवारों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए।'' ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पिछले पांच महीनों में 52,000 लोग मारे गए हैं। हालांकि, अपनी पोस्ट में ट्रंप ने यह नहीं बताया कि मुआवजे की राशि कैसे तय की जाएगी।

ईरान-जर्मनी के विदेश मंत्रियों ने बातचीत; मोजतबा खामेनेई ने छह अहम पदों पर की नियुक्तियां

तेहरान, एजेंसी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और उनके जर्मन समकक्ष जोहान वाडेफुल ने फोन पर बातचीत की। दोनों ने होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति और जारी संघर्ष को खत्म करने के तरीकों पर चर्चा की। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, बातचीत के दौरान अराघची ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा तभी सुनिश्चित हो सकती है, जब अमेरिका अपने सैन्य अभियान बंद करे। उन्होंने अमेरिका की ओर से ईरान के बंदरगाहों पर लगाई गई नाकाबंदी का भी जिक्र किया।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से यह भी कहा कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होता है, तो इसके कारण होने वाले सुरक्षा और आर्थिक नुकसान के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वहीं, जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने अराघची से क्षेत्रीय पड़ोसी देशों और अमेरिका के साथ बातचीत में रचनात्मक तरीके से शामिल होने की अपील की, ताकि संघर्ष को खत्म करने में मदद मिल सके। वाडेफुल ने आगे जोर देकर कहा कि समुद्री मार्ग से सभी जहाजों के लिए आने-जाने की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को बिना किसी शर्त के खोल दिया जाना चाहिए। इससे पहले रविवार को ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति संबंधी संसदीय समिति ने एक रणनीतिक पहल की व्यापक रूपरेखा को मंजूरी दी थी। इस पहल का मकसद फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में क्षेत्रीय सुरक्षा और टिकाऊ विकास को मजबूत करना है।

ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई 'पूरी तरह स्वस्थ': राष्ट्रपति पेजेशकियन : उधर, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने दावा किया कि देश के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई 'पूरी तरह स्वस्थ' हैं। उन्होंने उनकी शारीरिक स्थिति को लेकर लगाई जा रही अटकलों को खारिज किया। ईरान की समाचार एजेंसी आईएसएनए की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति पेजेशकियन ने कहा कि जो व्यक्ति सात से आठ घंटे तक बैठकर चर्चा कर सकता है, उसे स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी बताया कि खामेनेई के साथ उनकी 'बहुत अच्छी' बैठक हुई थी। यह उच्च स्तर की मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब मोजतबा खामेनेई की सेहत को लेकर लगातार खबरें और दावे सामने आ रहे थे। इससे पहले रविवार को ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी मेहर न्यूज एजेंसी ने एक बिना तारीख वाला वीडियो जारी किया था। इसमें मोजतबा खामेनेई को अच्छी सेहत में दिखाई दिए थे।

सर्वोच्च नेता खामेनेई ने सेना में छह अहम पदों पर नियुक्तियां कीं : इस बीच, ईरान के सर्वोच्च नेता और सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने सेना के जनरल स्टाफ, इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी और बसीज रेजिस्टेंस फोर्स में छह वरिष्ठ कमांडरों को अहम पदों पर नियुक्त किया है। यह जानकारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। खामेनेई ने अलग-अलग आदेश जारी कर इन नियुक्तियों की घोषणा की। अली अब्दोल्लाही को सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है, जबकि कियूमर्स हैदरी को डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है।

वहीं, अहमद वाहिदी को लेफ्टिनेंट जनरल के पद के साथ आईआरजीसी का कमांडर-इन-चीफ नियुक्त किया गया है। मुस्तफा इजादी को आईआरजीसी का डिप्टी कमांडर-इन-चीफ बनाया गया है। अली अजमाई को आईआरजीसी की नौसेना का कमांडर नियुक्त किया गया है, जबकि होसैन ताएब को बसीज रेजिस्टेंस फोर्स का प्रमुख बनाया गया है।

ईरानी विदेश मंत्रालय ने की अमेरिकी प्रतिबंधों की आलोचना : ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने मंगलवार को अमेरिका की प्रतिबंध नीति की आलोचना की। उन्होंने अमेरिकी प्रशासन पर आर्थिक प्रतिबंधों की 'लत' होने का आरोप लगाया। यह बयान अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की उस कथित टिप्पणी के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रतिबंध ईरान का 'दम घोंट' रहे हैं।

बघाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बार-बार प्रतिबंधों का इस्तेमाल यह दिखाता है कि अमेरिका कूटनीति के जरिये आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा, अमेरिकी वित्त मंत्री ने आर्थिक प्रतिबंधों के जरिये ईरान का 'दम घोंटने' की बात पर गर्व जताया है। इस दावे में दिखने वाली बेबसी से आगे बढ़कर देखें, तो यह अमेरिका की प्रतिबंधों की मजबूरी और लत का साफ सबूत है।

क्या ट्रंप बच्चों का जीवन खतरे में डाल रहे टीकाकरण पर लिया बड़ा फैसला, विरोध भी शुरू

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बच्चों के टीकाकरण को लेकर बड़ा कार्यकारी आदेश जारी किया है। इस आदेश में बचपन में लगाए जाने वाले टीकों की सिफारिशों को नए तरीके से तैयार करने की बात कही गई है। ट्रंप लंबे समय से इस विचार का समर्थन करते रहे हैं कि बच्चों को एक साथ कई टीके देने के बजाय उन्हें अलग-अलग चिकित्सकीय दौरों में लगाया जाना चाहिए। इसी सोच के तहत अब खसरा, गलसुआ और रूबेला यानी एमएमआर के टीके को भी तीन अलग-अलग टीकों के रूप में देने की योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। इस फैसले को लेकर अमेरिका में स्वास्थ्य विशेषज्ञों और प्रशासन के बीच बहस तेज हो गई है।

ट्रंप के आदेश में आखिर क्या बदलेगा : ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि बच्चों को लगने वाले टीकों को जहां संभव हो, अलग-अलग चिकित्सकीय मुलाकातों में दिया जाए। एमएमआर टीके को तीन अलग-अलग टीकों में बांटने की योजना बनाने का भी निर्देश दिया गया है। अमेरिका में फिलहाल खसरा, गलसुआ और रूबेला के लिए अलग-अलग टीका उपलब्ध नहीं है। आदेश में अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग को टीकों पर शोध बेहतर करने और अलग-अलग एमएमआर टीके उपलब्ध कराने की योजना तैयार करने को कहा गया है। ट्रंप ने इसे अभिभावकों के अधिकार, धार्मिक और संवैधानिक अधिकार तथा विज्ञान की जीत बताया है।

विशेषज्ञों को बच्चों के संक्रमण का डर क्यों है : सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि टीकों के बीच ज्यादा अंतर रखने से बच्चों के संक्रमण की चपेट में आने का खतरा बढ़ सकता है। उनका तर्क है कि अगर किसी बच्चे को एक बीमारी से बचाने वाला टीका मिल गया, लेकिन दूसरे टीके के लिए अगली मुलाकात तक इंतजार करना पड़ा, तो वह उस दौरान ऐसी बीमारी से संक्रमित हो सकता है, जिससे टीका बचाव कर सकता है। बच्चों के टीकों और उन्हें किस उम्र में तथा किस संयोजन में देना है, इनका लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है और इस्तेमाल के बाद भी उनकी सुरक्षा पर लगातार नजर रखी जाती है।

क्या ट्रंप ने वैक्सीन और ऑटिज्म को फिर जोड़ा : ट्रंप ने आदेश की घोषणा के दौरान वैक्सीन की संख्या और उन्हें देने के समय को अमेरिका में बढ़ रहे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जोड़ने की बात कही। हालांकि, इनपुट के अनुसार वैज्ञानिक सहमति और दशकों के अध्ययनों ने वैक्सीन और ऑटिज्म के बीच किसी संबंध को खारिज किया है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अध्यक्ष डॉ. एंड्रयू रेसिन ने कहा कि इस फैसले से ऐसी स्थिति में अनिश्चितता, डर और भ्रम पैदा हो रहा है, जहां इसकी जरूरत नहीं है।

क्या विरोधियों से डरने लगे पुतिन, यूक्रेन युद्ध का विरोध करने वाली पार्टी क्यों नहीं लड़ पाएगी चुनाव

तेल अवीव, एजेंसी। क्या अगले संसदीय चुनाव को लेकर पुतिन डर रहे हैं दरअसल ये सवाल तब उठा जब आज रूस की सुप्रीम कोर्ट ने याब्लोको पार्टी को अगले महीने होने वाले संसदीय चुनाव से बाहर कर दिया। अदालत ने उसका चुनावी पंजीकरण रद्द कर दिया। क्योंकि याब्लोको रूस की उन राजनीतिक ताकतों में रही है जो सरकार की नीतियों की आलोचना करती रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह यूक्रेन में रूसी सैन्य कार्रवाई का खुलकर विरोध करने वाली इकलौती पंजीकृत विपक्षी पार्टी थी। पिछले महीने केंद्रीय चुनाव आयोग ने याब्लोको को 10 अन्य पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी। लेकिन क्रेमलिन समर्थक मदरलैंड पार्टी की अपील के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अदालत ने याब्लोको को चुनावी मैदान से बाहर कर दिया। याब्लोको ने अपने चुनावी अभियान में युद्धविराम, कूटनीति और शांति की बात को प्रमुखता दी थी। पार्टी ने परमाणु युद्ध रोकने और रूस को डर तथा राजनीतिक दमन से मुक्त बनाने जैसे मुद्दे भी उठाए। पार्टी के सह-संस्थापक और राजनीतिक समिति के अध्यक्ष ग्रिगोरी याव्लिंस्की ने अदालत के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि याब्लोको को चुनाव से बाहर करना उन लोगों से संवाद से इनकार करने जैसा है, जो सरकार से असहज सवाल पूछते हैं। याव्लिंस्की ने कहा कि पार्टी इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। उनके मुताबिक रूस में शांति और आजादी की मांग को सरकार ने जितना समझा था, उससे ज्यादा समर्थन मिला है। रूस के कई क्रेमलिन समर्थक दलों ने यूक्रेन को लेकर याब्लोको के रुख की आलोचना की थी। ए जस्ट रूस पार्टी के प्रमुख सर्गेई मिरोनोव ने अभियोजक जनरल कार्यालय और न्याय मंत्रालय से याब्लोको की गतिविधियों की जांच करने की अपील की थी। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गेन्नेडी ज्युगानोव ने भी आरोप लगाया कि याब्लोको राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों का समर्थन नहीं करती। याब्लोको को चुनाव से बाहर करने के लिए मदरलैंड पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। उसने याब्लोको पर कॉपीराइट का उल्लंघन करने और चुनावी खर्च की सीमा पार करने का आरोप लगाया।

गौतम और सागर अदाणी के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में आपराधिक आरोप खारिज, फैसले पर क्या बोले उद्योगपति

न्यूयॉर्क, एजेंसी। अदाणी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने मंगलवार को अमेरिकी अदालत के आपराधिक आरोपों को खारिज करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया। अदाणी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इस चुनौतीपूर्ण दौर में सत्य, निष्पक्षता और कानून के शासन में उनका विश्वास अटूट रहा। रॉयटर्स के अनुसार, सोमवार को न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज निकोलस गारौफिस ने गौतम और सागर अदाणी के खिलाफ आपराधिक आरोप खारिज कर दिए। जज का यह फैसला संघीय अभियोजकों को आरोप वापस लेने का अधिकार देने के बाद आया। उन्होंने अभियोजकों से इसके कारणों के बारे में पूछताछ की थी। आरोपों को खारिज करते हुए जज ने कहा कि वह संतुष्ट हैं कि अदाणी ग्रुप की कथित निवेश प्रतिज्ञा ने न्याय विभाग के फैसले को प्रभावित नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपों को खारिज करने के संघीय अभियोजकों के निर्णयों की समीक्षा में जजों की भूमिका सीमित होती है।

गौतम अदाणी और अन्य के खिलाफ भारत में सौर ऊर्जा अनुबंधों से जुड़ी रिश्वतखोरी योजना का आरोप था। इसमें अमेरिकी निवेशकों को कथित तौर पर गुमराह करने की बात कही गई थी। इस साल मई में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इन आरोपों को खारिज करने की मांग की थी। इसके बाद न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के यूएस कोर्ट ने छश्छ्छ से जवाब मांगा था। इस जवाब की स्थिति को मजबूत किया, जिससे कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जज के रुख का समर्थन करेंगे।

इससे पहले 4 जुलाई को छश्छ्छ ने जज को बताया था कि गौतम अदाणी और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ आपराधिक मामला 'कभी नहीं लाया जाना चाहिए था'। छश्छ्छ ने अदालत से सभी आरोपों को स्थायी रूप से खारिज करने का आग्रह किया। उनका तर्क था कि अभियोजन कानूनी रूप से कमजोर था, मुख्य रूप से भारत केंद्रित था और अब न्याय के हितों की पूर्ति नहीं करता था। छश्छ्छ ने विस्तृत फाइलिंग में अपने पहले के अनुरोध का बचाव किया। विभाग ने कहा कि व्यापक समीक्षा के बाद 'खारिज करने का निर्णय स्पष्ट था'।मामला भारत से जुड़ा था, जिसमें 'कई भारतीयों ने कथित तौर पर अन्य भारतीयों को रिश्वत देने की कोशिश की थी, ताकि भारत में भारतीयों को भारतीय बिजली प्रदान करने के लिए भारतीय अनुबंध मिल सकें।

'संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व पुलिस होने का दिखावा कूटनीतिक तनाव पैदा कर सकता है और घरेलू चिंताओं पर बेहतर खर्च किए जाने वाले संसाधनों को भी बर्बाद करता है। भारत अपनी आंतरिक प्रणालियों को ब्रुकलिन और वाशिंगटन के अभियोजकों की तुलना में बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकता है।' DoJ ने यह भी कहा कि गौतम अदाणी और सागर अदाणी के खिलाफ प्रतिभूति धोखाधड़ी के आरोपों का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं था। उन्होंने कहा, 'प्रतिभूति आरोप कभी नहीं लाए जाने चाहिए थे।

हम अकेले बोझ नहीं उठाएंगे': चीन के बढ़ते दबदबे का असर, क्या एशिया को भी बेसहारा छोड़ रहा अमेरिका

मनीला, एजेंसी। पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एशिया में अपने सहयोगी देशों से रक्षा क्षेत्र में अधिक निवेश करने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ साझेदार के रूप में काम करना चाहता है न कि संरक्षित देशों के रूप में। अमेरिकी अधिकारी के इस बड़े बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या यूरोप की तरह अब अमेरिका एशिया में भी अपनी मौजूदगी को सीमित करने पर विचार कर रहा है गौरतलब बात ये है कि ये बयान ऐसे समय सामने आया है, जब चीन एशिया में अपना दबदबा लगातार बढ़ा रहा है और उसका कई एशियाई देशों के साथ समुद्री सीमा को लेकर विवाद चल रहा है।

अमेरिकी अधिकारी ने फिलीपींस में की ये टिप्पणी : अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन में अंडर सेक्रेटरी एल्ब्रिज कोल्बी ने फिलीपींस में एक कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी की। कोल्बी इन दिनों दक्षिण-पूर्व एशिया के दौरे पर हैं और अपने पहले पड़ाव पर वह फिलीपींस पहुंचे हैं। इसके बाद वह इंडोनेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया का दौरा करेंगे। कोल्बी ने यह भी दोहराया कि ईरान युद्ध और मध्य पूर्व में मौजूदा अमेरिकी व्यस्तताओं के बावजूद वाशिंगटन एशिया से पीछे नहीं हट रहा है। कोल्बी ने विदेशी राजनयिकों, सैन्य अधिकारियों, कारोबारियों और पत्रकारों की मौजूदगी वाले कार्यक्रम में कहा, 'अमेरिका बेशक एशिया से पीछे नहीं हट रहा है और हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित यहां हमारी स्थायी मौजूदगी की मांग करते हैं। हम जा नहीं रहे हैं; बल्कि हम यहां अपनी स्थिति और मजबूत कर रहे हैं, ताकि शक्ति संतुलन हमारे अनुकूल बना रहे। हम एशिया को बेहद अहम क्षेत्र मानते हैं।

चीन की आलोचना से किया परहेज : कोल्बी ने क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर अमेरिका की ओर से आमतौर पर की जाने वाली तीखी आलोचना से परहेज किया। इसमें विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियां भी शामिल हैं। वाशिंगटन पिछले कुछ वर्षों में फिलीपींस के तटरक्षक और नौसैनिक बलों के खिलाफ बीजिंग की बढ़ती आक्रामक कार्रवाइयों पर बार-बार चिंता जताता रहा है। चीन और फिलीपींस के साथ-साथ वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान दशकों से विवादित जलक्षेत्र को लेकर आमने-सामने हैं। यह जलमार्ग वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बीजिंग लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। उसने 2016 में फिलीपींस द्वारा शुरू किए गए मध्यस्थता मामले में आए उस फैसले को भी खारिज कर दिया है, जिसमें चीन के दावों को अमान्य कर दिया गया था। कोल्बी ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ द्वारा मई में सिंगापुर में आयोजित शांगरी-ला रक्षा सम्मेलन में दिए गए भाषण में जताई गई प्रतिबद्धता को दोहराया। हेगसेथ ने कहा था कि अमेरिका पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत रक्षा व्यवस्था तैयार करेगा। कोल्बी ने कहा कि 'अमेरिका यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि जहां सबसे ज्यादा जरूरत है।

भूकंप में अब तक 132 मौतें, 570+ घायल, दुनियाभर से मदद; तबाही पर मैक्रों-रुबियो क्या बोले

बोगोटा, एजेंसी। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने कई इलाकों को हिलाकर रख दिया। भूकंप के बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कम से कम 132 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। पश्चिमी कोलंबिया में आए इस भूकंप का असर पड़ोसी देश इक्वाडोर में भी महसूस किया गया। हादसे के बाद स्थानीय स्तर पर बचाव दल प्रभावित इलाकों में लोगों की तलाश में जुटे हैं। भूकंप की तबाही के बाद कई देशों के नेताओं ने कोलंबिया के लोगों के प्रति संवेदना और समर्थन जताया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में कोलंबिया फ्रांस की दोस्ती और मदद पर भरोसा कर सकता है। उन्होंने भूकंप में मारे गए लोगों, उनके परिवारों, घायलों और प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई। मैक्रों ने राहत और बचाव कार्य में जुटे लोगों की भी सराहना की।

यूक्रेन और इटली ने किस तरह जताई एकजुटता : यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी कोलंबिया के लोगों के साथ एकजुटता जताई। उन्होंने कहा कि पश्चिमी कोलंबिया में आए भूकंप की खबर बेहद दुखद है और इसका असर पड़ोसी इक्वाडोर पर भी पड़ा है। उन्होंने मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए दुनिया के सक्षम देशों से प्रभावित लोगों और देशों की मदद के लिए आगे आने की अपील की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी कहा कि वह कोलंबिया में आए भीषण भूकंप से जुड़ी खबरों पर नजर रख रही हैं और इटली प्रभावित परिवारों तथा बचाव कार्य में जुटे लोगों के साथ खड़ा है।

इक्वाडोर ने कोलंबिया को कितनी मदद की पेशकश की : भूकंप से प्रभावित कोलंबिया के लिए पड़ोसी इक्वाडोर ने तत्काल मदद की पेशकश की है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ अज़िन ने कहा कि उनका देश कोलंबिया के साथ खड़ा है। उन्होंने कोलंबिया की मदद के लिए 47 बचावकर्मियों, प्रशिक्षित कुत्तों और जरूरी उपकरणों वाली यूएसएआर टीम उपलब्ध कराने की पेशकश की। इस टीम के पास सात दिनों तक अभियान चलाने की क्षमता बताई गई है। इक्वाडोर ने कहा कि कोलंबिया की जरूरत के मुताबिक वह इस टीम को भेजने के लिए तैयार है।

राहत और बचाव अभियान के बीच क्या चुनौती है : भूकंप के बाद सबसे बड़ी चुनौती मलबे में फंसे लोगों तक पहुंचना और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कई लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं। ऐसे में बचाव दलों के सामने समय सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर, प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन और घायलों तक सहायता पहुंचाने का काम भी जारी है। कोलंबिया के साथ खड़े देशों की ओर से मदद की पेशकश के बीच अब स्थानीय प्रशासन के सामने राहत अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने की चुनौती है।

भूकंप के बाद दुनिया की नजर किस पर : 7.4 तीव्रता के भूकंप के बाद अब नजर लगातार चल रहे खोज और बचाव अभियान पर है। शुरुआती जानकारी में कम से कम 132 लोगों की मौत सामने आई है, लेकिन प्रभावित इलाकों में तलाश जारी रहने के कारण स्थिति आगे बदल सकती है। कोलंबिया के साथ फ्रांस, यूक्रेन, इटली, इक्वाडोर और अमेरिका की ओर से समर्थन जताया गया है। इक्वाडोर ने तो अपनी विशेष बचाव टीम भेजने की भी पेशकश की है।

रूस ने दिया भारत के साथ सीधे रेल मार्ग का प्रस्ताव, क्या हो सकता है रूट; किसे-कितना फायदा

मास्को, एजेंसी। रूस की तरफ से भारत को सीधा रेल रूट के जरिए जोड़ने पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में रूस के उप-प्रधानमंत्री मरात खुसनुलिन ने दोनों देशों के बीच एक संभावित रेल लिंक खड़ा करने पर गहराई से विचार की बात कही। उन्होंने इसके लिए विकल्प के तौर पर संभावित कुछ मार्ग भी सुझाए हैं। मजेदार बात यह है कि रूस और भारत के बीच एक सीधा रेल मार्ग खड़ा करने की यह चर्चाएं कोई नई नहीं हैं। इससे पहले भी दोनों देश व्यापार के लिए रेल आधारित मार्ग बनाने पर बात कर चुके हैं। व्यापार का कुछ हिस्सा रेल मार्ग के जरिए आता-जाता भी है, हालांकि यह मार्ग फिलहाल सीमित है और दोनों देशों के अंदर तक ही स्थित है, न कि अंतर्देशीय है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर रूस की तरफ से भारत के साथ रेल मार्ग स्थापित करने के लिए हाल ही में क्या बयान दिया गया है मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच व्यापार का क्या रूट है जिस नए रेल मार्ग की बात की जा रही है, उसका संभावित रूट क्या हो सकता है इसकी जरूरत क्यों महसूस की जा रही है और इस मार्ग को लेकर चर्चाओं का इतिहास क्या रहा है आइये जानते हैं...

सबसे पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया था एलान : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही बाल्टिक और बेरेंट्स सागर से लेकर सीधे हिंद महासागर तक एक सीधे रेलवे कॉरिडोर को स्थापित करने की विशाल बुनियादी ढांचा योजना की घोषणा कर चुके हैं। रूस के अधिकारियों के मुताबिक, घोषित प्रोजेक्ट का मकसद आधुनिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तैयार करना है जो मिस्र के पास वाले रास्ते-स्वेज नहर की तुलना में शिपिंग समय को लगभग आधा कर देगा और माल ढुलाई के खर्च को काफी कम करेगा।

अब उप-प्रधानमंत्री ने भी दोहराई रेल मार्ग की बात : ताजा बयान रूस उप-प्रधानमंत्री मरात खुसनुलिन का है, जिन्होंने बीते हफ्ते भारत तक एक सीधे रेल मार्ग के प्रस्ताव को व्यावहारिक बताया और कहा है कि इस रेल लिंक की संभावनाओं को तलाश जाना चाहिए । रूसी सरकार ने इस जमीन-आधारित रेल कॉरिडोर के लिए एक संभावित मार्ग भी साझा किया है।

1. पारंपरिक समुद्री मार्गः स्वेज नहर का रास्ता : यह दोनों देशों के बीच व्यापार का सबसे स्थापित और पुराना समुद्री मार्ग है। इसमें मालवाहक जहाज रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से निकल कर बोस्फोरस जलडमरूमध्य, भूमध्य सागर (मेडिटेरेनियन सागर), स्वेज नहर और लाल सागर से होते हुए मुंबई या भारत के अन्य पश्चिमी बंदरगाहों तक पहुंचते हैं। इस मार्ग से सफर पूरा होने में सामान्यतः 40 से 45 दिन या कुछ परिस्थितियों में 45 से 60 दिन का समय लगता है।

2. इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (आईएनएसटीसी) : यह समुद्र, रेल और सड़क मार्गों का एक संयुक्त मल्टीमॉडल नेटवर्क है। इसके तहत भारत के मुंबई से माल जहाजों द्वारा ईरान के बंदर अब्बास या चाबहार बंदरगाह तक भेजा जाता है। वहां से ईरान के रेल/सड़क मार्ग और कैस्पियन सागर के रास्ते माल को रूस के मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचाया जाता है।

चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा : यह मार्ग भारत के पूर्वी तट (खासकर चेन्नई) को रूस के सुदूर पूर्व में स्थित व्लादिवोस्तोक बंदरगाह से सीधे जोड़ता है। यह मार्ग स्वेज नहर के चक्करदार रास्ते को पूरी तरह बायपास करता है, जिससे समुद्री यात्रा का समय लगभग 18 से 20 दिन रह जाता है, जो कि पारंपरिक पश्चिमी मार्ग से लगभग 40 दिन का रहता है। हालांकि, इस मार्ग का इस्तेमाल भी सीमित व्यापार के लिए ही होता है। फिलहाल इसे कार्गो परिवहन के लिए बेहतर बनाए जाने की कोशिशें जारी हैं, ताकि व्यापार को और बढ़ाया जा सके। रूस अपने नए ट्रांस-आर्कटिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (टीएटीसी) के तहत इस आर्कटिक समुद्री मार्ग को तेजी से विकसित कर रहा है। भारत ने भी इस मार्ग में जबरदस्त रुचि दिखाई है। चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे को इस आर्कटिक मार्ग से जोड़कर भविष्य में रूस के उत्तरी क्षेत्रों से भारत के पूर्वी तटों तक कोयला, तेल, गैस और अन्य कच्चे माल की सुरक्षित और तेज आपूर्ति का नया नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। रूसी उप-प्रधानमंत्री मरात खुसनुलिन की ओर से सुझाया गया मार्ग पूरी तरह से जमीन के रास्ते भारत को रूस से जोड़ेगा। इसका संभावित भौगोलिक रूट रूस से तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते भारत आ सकता है। हालांकि, पाकिस्तान के साथ भारत की दूरियों के मद्देनजर उसे बायपास करने पर विचार किया जा सकता है।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी, 149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास, भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सतीश मराठा मर्डर केस

नवसारी से GPS खरीदकर अंकुर ने कार में फिट किया

हत्या में इस्तेमाल हथियारों के अलावा राहुल बटका के दोस्त से एक पिस्तौल बरामद

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सतीश मराठा हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस और क्राइम ब्रांच को जांच के दौरान चौंकाने वाली जानकारी मिली है। इस हत्याकांड की साजिश के तहत नवसारी से एक GPS ट्रैकिंग डिवाइस खरीदा गया था। राहुल मंडल ने राहुल बटका से कहा था कि यह GPS अंकुर पांडे को दे देना। अंकुर अच्छी तरह जानता था कि राहुल मंडल और सतीश के बीच संबंध अच्छे नहीं थे और दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था।

हत्या से करीब एक सप्ताह पहले जब सतीश की कार गैराज में आई थी, तब अंकुर ने मौका देखकर ड्राइविंग सीट के नीचे यह GPS डिवाइस फिट कर दिया था। इसका उद्देश्य सतीश की कार की लोकेशन ट्रैक करना और हत्या के लिए उसके ठिकाने की जानकारी हासिल करना था।

वारदात के समय आरोपी देसी, हाथ से बनी मैगजीन वाली पिस्तौल और देसी तमंचे समेत तीन हथियार लेकर सतीश की हत्या करने पहुंचे थे। हालांकि, जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने हत्या के लिए एक अतिरिक्त पिस्तौल भी बैकअप के तौर पर रखी थी।

यह चौथी पिस्तौल आरोपी राहुल बटका ने अपने दोस्त सत्यनारायण के पास छिपाने के लिए रखी थी। हालांकि हत्या में इस पिस्तौल का सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ था, फिर भी पुलिस ने गहन जांच के बाद इसे भी बरामद कर लिया है।

सनसनीखेज हत्या के बाद क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस ने कई जगह छापेमारी कर पांच मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें राहुल उर्फ आर.के. कपूर, केतन सरसात, राहुल बटका, करण दुबे और अजीत गोस्वामी शामिल हैं।

इसके अलावा हत्या में शामिल चार कानून के संघर्ष में आए नाबालिगों को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की है।

गिरफ्तार सभी आरोपियों का पांच दिन का पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद भेस्तान पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए दोबारा रिमांड की मांग करते हुए कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, कोर्ट ने अतिरिक्त रिमांड मंजूर नहीं किया और सभी मुख्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत यानी जेल भेजने का आदेश दिया।

दो महीने में CP और म्युनिसिपल कमिश्नर का तबादला

मनपा के 15 से ज्यादा महत्वपूर्ण पद स्थायी अधिकारियों के बिना खाली

सिटी इंजीनियर से लेकर 6 जोन के AC तक प्रभार में

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

स्मार्ट सिटी सूरत में पिछले दो महीनों से प्रशासनिक व्यवस्था प्रभारी अधिकारियों के भरोसे चल रही है। शहर की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था के दो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों—पुलिस कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर—का कम समय में तबादला कर दिया गया है। 1 जुलाई को तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अनुपमसिंह गहलोत और इसके बाद 11 अगस्त को म्युनिसिपल कमिश्नर एम. नागराजन के तबादले के बाद फिलहाल दोनों पदों की जिम्मेदारी प्रभारी अधिकारियों के पास है। वर्तमान में म्युनिसिपल कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार सूरत के कलेक्टर तेजस परमार को सौंपा गया है। हालांकि, सूरत मनपा की स्थिति भी इससे अलग नहीं है।

सूरत महानगरपालिका में वित्तीय फैसलों, करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं और तकनीकी कार्यों को संभालने वाली मुख्य रीढ़ जैसी शाखाएं भी प्रभारी अधिकारियों के भरोसे चल रही हैं। मनपा के आर्थिक लेन-देन संभालने वाले चीफ अकाउंटेंट (जिग्नेश पटेल), शहर के ब्रिज और सड़क जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी संभालने वाले सिटी इंजीनियर (महेश चावड़ा), टाउन प्लानर और शहर विकास अधिकारी जैसे बेहद संवेदनशील पदों पर स्थायी अधिकारी नहीं हैं। इसके अलावा IT डायरेक्टर, चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, PRO और म्युनिसिपल सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी अतिरिक्त प्रभार देकर चलाए जा रहे हैं।

लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं और जोन स्तर की नागरिक सुविधाओं से सीधे जुड़े प्रशासन में भी गंभीर स्थिति बनी हुई है। शहर के सेंट्रल, कतारगाम, वराछा, सरथाणा, उधना-ए और कनकपुर—इन कुल 6 जोन में स्थायी असिस्टेंट कमिश्नर नहीं हैं। इसके चलते अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है।

हाईटेक और तेजी से विकसित हो रहे सूरत शहर में रोजाना करोड़ों रुपये की परियोजनाओं का काम और नागरिकों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ऐसे में स्थायी अधिकारियों की कमी के कारण महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों और विकास कार्यों में देरी होने की आशंका जताई जा रही है।

मनपा के अलावा सूरत की शिक्षा समिति में भी स्थायी अधिकारियों की भारी कमी के बीच वर्षों से अतिरिक्त प्रभार के जरिए काम चलाया जा रहा है। शहर के 350 से अधिक प्राथमिक और सुमन स्कूलों के नेटवर्क, 4,500 से अधिक शिक्षकों के प्रबंधन और 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य की जिम्मेदारी संभालने वाले शासनाधिकारी और उपशासनाधिकारी—दोनों पदों पर फिलहाल प्रभारी अधिकारी नियुक्त हैं।

तंत्र द्वारा स्थायी नियुक्तियां करने के बजाय अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपकर काम चलाने से शैक्षणिक प्रशासन और स्कूलों के संचालन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।

युवक की मौत के मामले में परिवार का भेस्तान पुलिस पर गंभीर आरोप

29 तारीख को लापता संजीव कुमार का 14 दिन बाद मिला शव

PI बोले- दोनों मामलों में विधिवत शिकायत दर्ज की गई

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत के भेस्तान इलाके के गणेशनगर में रहने वाले 40 वर्षीय संजीव कुमार सिंह 29 तारीख को अपनी मिल में ड्यूटी पूरी करने के बाद रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। संजीव कुमार के घर नहीं पहुंचने पर परिवार ने उनकी तलाश शुरू की। परिजनों ने स्थानीय भेस्तान पुलिस चौकी से संपर्क किया, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में यह कहते हुए शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया कि अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं। इसके चलते परिवार को कई चक्कर लगाने पड़े।

जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना में तैनात मृतक के भाई राजीव कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करती रही। सभी जरूरी दस्तावेज होने के बावजूद पुलिस ने महिला यानी मृतक की पत्नी से ही पांच लोगों को तलाश कर लाने के लिए कहा और उसे परेशान किया। आखिरकार दबाव बनाने के बाद 31 तारीख को पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। परिवार का आरोप है कि इसके बावजूद पुलिस ने आसपास के इलाके में प्राथमिक जांच करने की भी जहमत नहीं उठाई।

मामले का कोई समाधान नहीं निकलने पर देश की सीमा पर तैनात मृतक के छोटे भाई और असम राइफल्स के जवान राजीव कुमार 7 तारीख को सूरत पहुंचे। उन्होंने खुद स्थानीय पुलिस स्टेशनों और चौकियों में संजीव की तलाश शुरू की। जब वह घटनास्थल से महज करीब 1.8 किलोमीटर दूर स्थित उना पाटिया पुलिस चौकी पहुंचे तो गेट के बाहर संजीव कुमार की तस्वीर और पोस्टर लगे दिखाई दिए। PSI से बातचीत करने पर उन्हें पता चला कि संजीव कुमार का शव दुर्घटना के बाद 29 तारीख को ही बरामद हो चुका था।

भेस्तान पुलिस चौकी और उना पाटिया पुलिस चौकी के बीच महज 1 से 1.8 किलोमीटर की दूरी होने और दोनों का प्रभारी एक ही अधिकारी होने के बावजूद परिवार को 14 दिनों तक कोई जानकारी नहीं दी गई। परिवार का आरोप है कि यदि दोनों चौकियों के बीच उचित समन्वय होता तो 29 या 30 तारीख को ही शव की पहचान हो सकती थी।

14 दिन बाद सिविल अस्पताल से बेहद खराब हालत में शव मिलने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का आरोप है कि 29 तारीख को ही रेलवे ट्रैक से शव मिलने के बावजूद भेस्तान पुलिस ने उन्हें 14 दिनों तक अंधेरे में रखा।

आर्मी जवान राजीव कुमार ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि देश की सुरक्षा करने वाले सैनिक के परिवार के साथ पुलिस ऐसा व्यवहार करती है, तो आम नागरिकों के साथ क्या होता होगा? उनका आरोप है कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय पीड़ित परिवार को ही इधर-उधर भटकाया।

परिवार ने पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हुए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और न्याय की मांग की है।

भेस्तान के PI एस.बी. देसाई ने बताया कि शुरुआत में जब अज्ञात शव मिला था, तब पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया था और उस समय शव की पहचान नहीं हो पाई थी। इसी दौरान मृतक के परिवार ने संजीव कुमार के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, दुर्घटना में मौत हुई व्यक्ति ही लापता संजीव कुमार है, इसकी जानकारी शुरुआत में नहीं थी। बाद में पुलिस जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया और पुलिस ने दोनों मामलों में विधिवत शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

सुरत मनपा के दो बड़े फैसले

मैदान नहीं होने वाले 70 स्कूलों में छत पर ध्वजारोहण पर रोक

सीधी भर्ती में पूर्व सैनिकों को मिलेगा आरक्षण

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत महानगरपालिका ने दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मैदान की सुविधा नहीं होने वाले मनपा संचालित 70 स्कूलों में अब छत पर ध्वजारोहण करने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा मनपा की सीधी भर्ती में पूर्व सैनिकों को आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है।

सूरत महानगरपालिका ने शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्र में दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। हाल ही में सुमन स्कूल में छत पर करंट लगने से एक छात्र की हुई दुखद मौत के बाद 15 अगस्त को छत पर ध्वजारोहण करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, मनपा की सीधी भर्ती में पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षण देने का प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

स्कूल की छत पर ध्वजारोहण पर प्रतिबंध

सुमन स्कूल की दुखद घटना के बाद बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा समिति के चेयरमैन राजेंद्र कपाड़िया ने यह निर्णय घोषित किया है। शिक्षा समिति की 350 स्कूलों में से मैदान की सुविधा नहीं होने वाली 70 स्कूलों में अब तक छत पर स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाता था। अब इन स्कूलों को छत पर कार्यक्रम आयोजित करने के बजाय नजदीकी मैदान वाली स्कूल में अथवा मनपा के मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का निर्देश दिया गया है।

मनपा की सीधी भर्ती में पूर्व सैनिकों को आरक्षण का प्रस्ताव

गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की 22 जनवरी 2018 की अधिसूचना और हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर सूरत महानगरपालिका ने स्थायी भर्ती में पूर्व सैनिकों को आरक्षण देने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत वर्ग-1 और वर्ग-2 के पदों पर 1% आरक्षण, वर्ग-3 में 10% आरक्षण और वर्ग-4 में 20% आरक्षण का प्रावधान लागू होगा।

यह प्रस्ताव स्थायी समिति और सामान्य सभा की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा। साथ ही भविष्य में राज्य सरकार द्वारा आरक्षण के नियमों में किए जाने वाले बदलावों को लागू करने के लिए नगर आयुक्त को अधिकृत किया जाएगा।

खाने को लेकर मामूली कहासुनी में सुरत में खूनी खेल

दोस्त ने ही चाकू से वार कर उतारा मौत के घाट,

डिंडोली पुलिस ने फरार 2 आरोपियों और 1 नाबालिग को पकड़ा

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत शहर के डिंडोली, नवागाम स्थित लक्ष्मणनगर इलाके में देर रात खूनी वारदात हुई। गत 30 जुलाई 2026 को रात करीब पौने एक बजे प्रवीण उर्फ आंबा शिरसाठ (कोली) और उसके दोस्त भूषण उर्फ बबलू बंसीलाल पाटील के बीच महज खाना खाने को लेकर मामूली कहासुनी हुई थी। देखते ही देखते यह कहासुनी विवाद में बदल गई।

आरोप है कि इसी रंजिश में भूषण उर्फ बबलू पाटील ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रवीण पर चाकू से गले और शरीर के अन्य हिस्सों पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल प्रवीण की मौत हो गई। इस मामले में मृतक के भाई ने डिंडोली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

वारदात की गंभीरता को देखते हुए डिंडोली पुलिस स्टेशन के पीआई के निर्देश पर सर्विलांस टीम ने तत्काल जांच शुरू कर दी। मामले में फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने मुखबिरों और सर्विलांस नेटवर्क की मदद ली। आखिरकार डिंडोली पुलिस टीम ने तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर छापेमारी कर फरार दो मुख्य आरोपियों समेत एक कानून के संघर्ष में आया नाबालिग किशोर को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस द्वारा पकड़े गए मुख्य आरोपियों में 23 वर्षीय किशन महेंद्र राजभर शामिल है। वह प्लॉट नंबर 58, लक्ष्मणनगर, नवागाम, डिंडोली में रहता है और मूल रूप से वाराणसी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दूसरा आरोपी 32 वर्षीय अरुण उर्फ चिंटू उर्फ कालिया मुन्नीलाल प्रजापति है। वह मजदूरी करता है और लक्ष्मणनगर, डिंडोली तथा तातिथैया, कडोदरा में रहता है। वह भी मूल रूप से वाराणसी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।

इसके अलावा पुलिस ने कानून के संघर्ष में आए एक नाबालिग किशोर को भी हिरासत में लिया है। पकड़े गए आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के रहने वाले हैं और सुरत में मजदूरी के लिए रह रहे थे।

सोशल मीडिया पर दोस्ती पड़ी महंगी

स्नैपचैट के जरिए शादीशुदा महिला को जाल में फंसाकर

2.80 लाख रुपये और सोने के जेवर ऐंठे,शारीरिक शोषण का भी आरोप

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत के कपोद्रा इलाके में सोशल मीडिया ऐप 'स्नैपचैट' के जरिए हुई दोस्ती एक शादीशुदा महिला के लिए गंभीर मुसीबत बन गई। कपोद्रा में रहने वाली महिला की फरवरी 2026 में जकातनाका निवासी टोनीश उर्फ जैनिल घनश्यामभाई पडसाला से पहचान हुई थी। विश्वास में लेने के बाद आरोपी पर ब्लैकमेलिंग, दुष्कर्म और लाखों रुपये व सोने के आभूषण ऐंठने का आरोप लगा है। इस मामले में कपोद्रा पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार किया है।

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी टोनीश ने पहले साइबर क्राइम के मामले में खुद के फंसने का झूठा नाटक किया और पुलिस तथा वकीलों को पैसे देने के बहाने महिला से रकम मांगी। इसके बाद उसने महिला के पति को स्नैपचैट के स्क्रीनशॉट दिखाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

इसी तरह डर दिखाकर आरोपी ने अलग-अलग चरणों में महिला से 2.80 लाख रुपये नकद ऐंठ लिए। आरोप है कि इसके बाद भी वह नहीं रुका और महिला की इच्छा के विरुद्ध जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी की लालच बढ़ती गई और उसने महिला को धमकाकर सोने की रुद्राक्ष माला, पाटला, मंगलसूत्र, अंगूठियां, हार, बालियां, कड़ली, पोचा और पेंडल समेत कई कीमती सोने के आभूषण जबरन उतरवा लिए।

आभूषण ऐंठने की इस पूरी साजिश में टोनीश का दोस्त आशीष वेकरिया भी उसके साथ शामिल होने का आरोप है।

आरोपियों के कथित मानसिक, आर्थिक और शारीरिक उत्पीड़न से परेशान होकर महिला ने आखिरकार कपोद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कपोद्रा पुलिस ने केस दर्ज करने के कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपी टोनीश उर्फ जैनिल पडसाला और उसके साथी आशीष वेकरिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

सुरत में दो दिन आधे से 1 इंच बारिश का अनुमान

उकाई डैम का जलस्तर 334.54 फीट पर स्थिर

आवक कम होने से गेट अभी बंद

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

गुजरात के ऊपर सक्रिय हुई नई बारिश प्रणाली के चलते मौसम विभाग ने सूरत शहर में अगले दो दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान शहर में आधे से 1 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मंगलवार को दिनभर बादल छाए रहने के बाद देर शाम आसमान में काले घने बादल छा गए और धीमी बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई।

दक्षिण गुजरात की जीवनरेखा माने जाने वाले उकाई डैम का जलस्तर फिलहाल 334.54 फीट पर स्थिर है। डैम में ऊपरी क्षेत्र से 3,000 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है, जबकि हाइड्रो पावर स्टेशन के जरिए 17 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मौजूदा जलस्तर 335 फीट के रूल लेवल के बेहद करीब पहुंच गया है। हालांकि, ऊपरी क्षेत्र से पानी की आवक सामान्य से कम होने के कारण इस सीजन में अभी तक डैम के गेट खोलकर पानी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी है।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को सूरत शहर में अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन के दौरान दक्षिण-पश्चिम दिशा से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। वातावरण में नमी बढ़ने के साथ ही शहर में बारिश का माहौल और अधिक गहराता जा रहा है।